घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 152- शनिवार 04- अप्रैल 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

"बस्तर की यह नई पहचान आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यह क्षेत्र अब शांति, प्रगति और गौरव की राह पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हम कृतज्ञ हैं......

माँ दंतेश्वरी और जनजातीय नायक वीर गुण्डाधुर की यह धरती छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 को माओवादी आतंक से मुक्त हुई है। हिंसक माओवादी विचारधारा ने न जाने कितनी माँओं की कोख उजाड़ दी, बहनों का सुहाग और मासूमों के सिर से पिता का साया छीन लिया। देश के लिए लड़ते हुए हजारों जवान शहीद हुए। दशकों से सशस्त्र माओवाद देश के विकास को खोखला करता रहा, वर्ष 2014 में आपके आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और दृढ़ संकल्प तथा सुनियोजित रणनीति के माध्यम से माओवादी हिंसा पर कठोर प्रहार किया गया। अनेक राज्य सशस्त्र माओवाद से मुक्त हुए लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ महतारी और हमारे पड़ोसी राज्यों में यह नासूर बचा हुआ था। आपने पुनः आशीर्वाद दिया और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाई। पिछले ढाई सालों में आपकी सरकार ने सामूहिक संकल्प के बल पर इस सशस्त्र माओवादी नासूर को नष्ट कर दिया।

हम कृतज्ञ हैं उन शहीद जवानों के प्रति, जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति देकर देश को माओवाद से मुक्ति दिलाई। हम कृतज्ञ है हमारे सुरक्षा बल के जवानों के प्रति, जिन्होंने साहस और संकल्प के साथ अपनी जान पर खेलकर माओवाद की जड़ पर कड़ा प्रहार करके उसका समूल नाश किया।

हम कृतज्ञ हैं बस्तर की जनता का, जिन्होंने माओवादी हिंसा को न केवल अस्वीकार किया अपितु उसके विरोध में खड़े हुए। मुझे आपका जज्बा याद आता है जब सशस्त्र माओवादियों द्वारा वोट देने पर ऊंगली काट देने की धमकी दी जाती थी, तब भी आप निर्भय होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करते थे। आपके मतदान से एक ऐसा नेतृत्व आया जिसने एक दशक के भीतर आंतरिक सुरक्षा के इस सबसे बड़े संकट को समाप्त कर दिया।

हम कृतज्ञ हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसपूर्ण नेतृत्व के प्रति। मुझे याद है वर्ष 2015 में दंतेवाड़ा में उन्होंने अपनी सभा में हथियार उठाने वाले युवाओं से कहा था 'एक प्रयोग कीजिए, पांच दिन हथियार रख दीजिए, उस परिवार के बच्चे के साथ दिन गुजारिए जिसने आपकी वजह से अपने परिजनों को खोया है फिर आप कभी हिंसा के रास्ते में नहीं जाएंगे।'

प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया, मार्गदर्शन किया है। उनके दृढ़ संकल्प की बदौलत देश माओवादी हिंसा से मुक्त हुआ है। हिमालय जैसी चुनौतियों से निपटने के उनके साहस ने हमें उत्साह से भर दिया और हमने यह असंभव जैसा लक्ष्य प्राप्त किया।

हम कृतज्ञ हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के , जो माओवादी नासूर को नष्ट करने के लिए बनायी गई रणनीति के शिल्पी हैं । रायपुर में पत्रकारों की भरी सभा में आपने देश से वायदा किया था कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करेंगे और इसे पूरा किया। आपने माओवादी आतंक को नष्ट करने के लक्ष्य पर नजर टिकाए रखी। हमारा नेतृत्व किया, संसाधन और मार्गदर्शन दिया। हमारे बहादुर जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। आपने गोली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बोली से देने का संदेश दिया। माओवादी हिंसा को छोड़कर जो शांति की राह पर लौटे, संविधान को अपनाया, उनका हमने स्वागत किया।

हम कृतज्ञ हैं प्रदेश की जनता के प्रति जो इस सुंदर धरती को सशस्त्र माओवाद से मुक्त कराने के रास्ते में सहभागी बनी, आपने हम पर विश्वास किया। विश्वास कीमती होता है, हमने इसकी रक्षा की है। बस्तर में बच्चे अब निर्भय होकर स्कूल जाएंगे, माताएं-बहनें आजादी की सांस लेंगी और हर तरफ विकास का उजाला फैलेगा।

अब कहीं रेड कॉरिडोर नहीं, हर तरफ ग्रीन कॉरिडोर है।

एक सुखद उज्ज्वल भविष्य की राह पर हम सब सहभागी बन अब आगे बढ़ेंगे।

जय भारत, जय छत्तीसगढ़

आपका **विष्णु देव साय** मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

संवाद:- 47391/61

CMYK

संपादकीय

बंगाल में मुस्लिम मतों का रुझान

बंगाल के मुसलमानों के पास तृणमूल कांग्रेस के समानांतर एक विकल्प उपलब्ध हो गया है...हुमायूं कबीर के साथ कुछ प्रभावी मुसलमान नेता और चेहरे आ गए हैं...कुल मिलाकर देखें तो मुस्लिम राजनीति को लेकर सामूहिक सोच तथा माहौल में पिछले तीन चुनावों से अंतर है...

इ पश्चिम बंगाल चुनाव का एक प्रमुख विश्लेषण हमेशा मुस्लिम मतों पर केंद्रित रहता है। कई वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निरंतर विजय में मुस्लिम मतों की प्रमुख भूमिका मानी जाती रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल की आबादी करीब 9.13 करोड़ थी, जिसमें मुस्लिम लगभग 2.5 करोड़ थे। इस समय बंगाल की कुल जनसंख्या 10.5 करोड़ से ऊपर होगी, जिसमें मुस्लिम तीन करोड़ से अधिक हो सकते हैं। बंगाल में मुस्लिम बहुल जिले हैं मुर्शिदाबाद-66.3 प्रतिशत, मालदा-51.3, उत्तर दिनाजपुर-50, बीरभूम-37, दक्षिण 24 परगना-35.5 और नादिया-26.7 प्रतिशत।

यदि भाजपा जबरदस्त टक्कर देने के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता को नहीं हिला पाई तो उसका एक कारण मुस्लिम वोट भी थे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम से गठबंधन कर उसे आठ सीटें दी हैं। हुमायूं कबीर ने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ सौ से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पिछली बार फुरफुरा शरीफ के इमाम ने भी अपनी पार्टी बनाकर कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ गठबंधन किया था, पर उनका भी प्रभाव नहीं पड़ा और मुसलमान कुल मिलाकर तृणमूल के साथ ही गए। मुसलमान भाजपा को हराने के लिए मतदान करते हैं।

प्रश्न है कि इस बार मुस्लिम मतों की प्रवृत्ति किस ओर रहेगी? अगर पिछले विधानसभा चुनाव को आधार बनाएं तो मुर्शिदाबाद,मालदा,उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और साउथ 24 परगना जैसे जिलों में 85 ऐसी सीटें हैं, जिन पर मुस्लिम जनसंख्या 35 प्रतिशत से ज्यादा है। इनमें से 75 सीटें तृणमूल के पास हैं। जितनी आक्रामक होकर तृणमूल मुसलमानों के साथ खड़ी होती है, उससे उनका ध्रुवीकरण उसके पक्ष में बनता है। मुर्शिदाबाद में पिछले वर्ष हिंदू विरोधी भयानक दंगे में जब लोग पलायन करने को मजबूर थे,तब ममता कोलकाता में इमामों और मौलवियों की सभा में दंगों के लिए भाजपा और आरएसएस को दोषी ठहरा रही थीं। बंगाल में सीएए विरोधी आंदोलन के समय भी भारी हिंसा हुई थी, पर ममता सरकार ने उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की।

एनआरसी और सीएए का भय दिखाकर ममता मुसलमानों को आभास दिलाती रहती हैं कि उनके सत्ता में रहने से ही वे सुरक्षित हैं। मुसलमानों को साथ रखने के लिए भाजपा का भय उनका बहुत बड़ा अस्त्र है। 2011 के चुनाव में ममता ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था। दो साल बाद उन्होंने घोषणा की कि रिपोर्ट का 90 प्रतिशत हिस्सा लागू किया जा चुका है। शायद ही किसी राज्य सरकार ने इतनी त्वरित गति से ऐसा किया हो। हर चुनाव में ममता मुसलमानों के लिए कुछ नई घोषणाएं करती हैं। आचार संहिता लागू होने से दो दिन पहले ही उन्होंने इमामों का भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। मुस्लिम छात्र-छात्राओं की स्कालरशिप के लिए वे विशेष योजना चलाती हैं। चुनाव से पहले अंतरिम बजट में भी उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के लिए 5,700 करोड़ रुपये जारी किए।

मुसलमानों के सामने यह साफ है कि अगर तृणमूल हारती है तो सत्ता में भाजपा आएगी। इससे मुस्लिम मतों के तृणमूल के साथ जाने के ही संकेत मिलते हैं, किंतु हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी बंगाल में एक नया प्रयोग है। बाबरी मस्जिद की नींव रखते समय एकत्रित भारी भीड़ से माहौल भी बनता दिखा था। कबीर मुसलमानों के बीच अपने चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपने कुल 291 उम्मीदवारों में 47 मुस्लिम उतारे हैं। यानी करीब 18 प्रतिशत। पिछली बार की तरह ममता ने मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों से भी हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं। वस्तुतः ममता ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट कभी नहीं दिए। इसे हुमायूं कबीर, ओवैसी और अन्य मुस्लिम नेता मुद्दा बना रहे हैं। कहना कठिन है कि यदि हुमायूं कबीर का गठबंधन सौ से ऊपर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करता है तो उसका कुछ तो असर होगा ही।

सीबीआई की सीमाएं और सवाल

जब जांच एजेंसी बन जाए राजनीति का केंद्र बिंदु...

भारत के संघीय ढांचे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का राज्य क्षेत्राधिकार एक ऐसा संवेदनशील और बहुपरतीय मुद्दा बन चुका है,जो केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं है,बल्कि राजनीतिक,संवैधानिक और नैतिक प्रश्नों को भी अपने भीतर समेटे हुए है...पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह विभिन्न राज्यों–विशेषकर विपक्षी शासित राज्यों–ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति (जनरल कंसेंट) वापस ली है,उसने इस बहस को और अधिक तीखा बना दिया है...यह सवाल बार-बार उठाया जा रहा है कि क्या सीबीआई वास्तव में एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है या फिर वह केंद्र सरकार के प्रभाव में काम करने वाली संस्था बनती जा रही है...दूसरी ओर,केंद्र सरकार का यह दावा है कि राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार जांच एजेंसियों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। सच इन दोनों अतियों के बीच कहीं स्थित है...

डॉ.प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

सी बीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को समझने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम,1946 (डीएसपीई अधिनियम) को समझना आवश्यक है। यही वह कानून है जो सीबीआई को वैधानिक आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी राज्य में सीबीआई को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होगी। यही प्रावधान भारतीय संघवाद की उस भावना को दर्शाता है, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान किया गया है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह सहमति पूर्ण और अपरिहार्य नहीं है। कानून में ऐसे कई अपवाद मौजूद हैं, जहां सीबीआई बिना राज्य की सहमति के भी जांच कर सकती है।

उदाहरण के लिए,यदि किसी मामले में उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय सीबीआई जांच का आदेश देता है,तो राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त,केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में, या केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में भी सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि राज्य की शक्ति सीमित है और उसे राष्ट्रीय हित तथा न्यायिक प्रक्रिया के सामने झुकना पड़ सकता है।

भारतीय संविधान का संघीय ढांचा भी इस पूरे विवाद को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को एक सहकारी संघवाद का उदाहरण माना जाता है,लेकिन यह पूर्णतः विकेंद्रीकृत नहीं है। सातवीं अनुसूची में कानून-व्यवस्था को राज्य सूची में रखा गया है,जिसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थितियों में यह राज्यों का विषय है। लेकिन अनुच्छेद 246 और 254 के तहत केंद्र को विशेष परिस्थितियों में प्रधानता प्राप्त है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि राष्ट्रीय एकता और कानून का शासन किसी भी स्थिति में कमजोर न पड़े।

यहीं से यह टकराव उत्पन्न होता है। एक ओर राज्य अपनी संवैधानिक स्वायत्तता का हवाला देते हैं,वहीं दूसरी ओर केंद्र यह तर्क देता है कि राष्ट्रीय हित और व्यापक न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उसके पास हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। 2018 के बाद से पश्चिम बंगाल,पंजाब,तेलंगाना, केरल,झारखंड,राजस्थान,छत्तीसगढ़ और अन्य कई राज्यों ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। सामान्य सहमति का अर्थ होता है कि सीबीआई राज्य में बिना हर बार अनुमति लिए जांच शुरू कर सकती है। इसकी वापसी के बाद सीबीआई को हर मामले में अलग से अनुमति लेनी पड़ती है,जिससे जांच प्रक्रिया धीमी और जटिल हो जाती है।

राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है। कई मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अचानक जांच शुरू हो जाती है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं के मामलों में ढिलाई बरती जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में सामान्य सहमति वापस लेते समय इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की थी। इसी तरह अन्य राज्यों ने भी इसे अपनी स्वायत्तता की रक्षा का कदम बताया।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकारें सहमति रोककर भ्रष्टाचार और अपराध की जांच में बाधा डाल रही हैं। यदि हर मामले में राजनीतिक अनुमति की आवश्यकता होगी, तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2021 में इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने से अंतरराज्यीय और जटिल अपराधों की जांच प्रभावित होती है। यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं,बल्कि व्यापक न्यायिक हितों के संदर्भ में देख रही है।

इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू यह है कि इससे जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। जब किसी जांच एजेंसी पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं,तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि सीबीआई को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं देखा जाएगा, तो उसके द्वारा की गई जांच और कार्रवाई भी संदेह के घेरे में आ जाएगी।

इसके साथ ही,राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने की प्रवृत्ति भी एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यदि हर राज्य अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों को प्रवेश से रोकने लगे, तो राष्ट्रीय स्तर पर अपराध नियंत्रण और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे अपराध जो कई राज्यों में फैले होते हैं, उनकी जांच के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता होती है।

समाधान इस टकराव में नहीं, बल्कि संतुलन और सहयोग में निहित है। सबसे पहले,यह आवश्यक है कि सीबीआई की स्वायत्तता को वास्तविक रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है और एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है,जिसमें न्यायपालिका और विपक्ष की भी भागीदारी हो। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सीबीआई किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करे।

दूसरे,डीएसपीई अधिनियम में संशोधन कर एक स्पष्ट और संतुलित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि राज्य सरकारें सहमति देने या न देने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय लें। यदि निर्धारित समय में कोई निर्णय नहीं लिया जाता,तो उसे स्वीकृति माना जाए। इससे जांच प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को रोका जा सकता है।

तीसरे,अंतरराज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं को सक्रिय किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के विवादों का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सके। सहकारी संघवाद का वास्तविक अर्थ यही है कि केंद्र और राज्य मिलकर समस्याओं का समाधान करें, न कि एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हों।

अंततः,यह समझना आवश्यक है कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केवल एक कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा भी है। यदि केंद्र और राज्य दोनों अपने-अपने अधिकारों के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें,तो इस विवाद का समाधान संभव है। न तो पूर्ण केंद्रीकरण उचित है और न ही पूर्ण विकेंद्रीकरण। एक संतुलित,पारदर्शी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण ही इस समस्या का स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है।

जब तक यह संतुलन स्थापित नहीं होता,तब तक सीबीआई का अधिकार क्षेत्र संघवाद और केंद्रीकरण के बीच खींचतान का प्रतीक बना रहेगा। लेकिन यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत सुधारों के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किए जाएं, तो यह विवाद न केवल सुलझ सकता है, बल्कि भारतीय संघीय ढांचे को और अधिक मजबूत भी बना सकता है।

पीडीए के सहारे नेताजी से कैसे आगे निकल सकते हैं अखिलेश

अजय कुमार
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह यादव का नाम हमेशा सियासत के एक बड़े खिलाड़ी के रूप में याद किया जाता है,जो एक शिक्षक के साथ अच्छे पहलवान भी थे। कुश्ती के अखाड़े से निकलकर राजनीति के मैदान में उतरे मुलायम विरोधियों को धूल चटाने का हुनर रखते थे। इटावा जिले के छोटे से गांव सैफई से निकलकर मुलायम ने यूपी और दिल्ली की राजनीति तक में अपना दबदबा बनाए रखा था,लेकिन उनकी सियासत को संभालने वाले उनके पुत्र अखिलेश यादव नेताजी की सियासत के करीब भी भटकते हुए नजर नहीं आते हैं। सियासत में 15 साल का लंबा सफर तय करने के बाद भी अपने दमखम पर समाजवादी पार्टी को कोई बड़ी विजय का स्वाद नहीं चखा पाए हैं। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी दो विधानसभा और तीन लोकसभा के चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन कुछ हद तक 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा किसी भी चुनाव में अखिलेश की हनक-धमक नहीं सुनाई दी,जबकि सपा को मजबूत करने के लिए अखिलेश ने कांग्रेस और मायावती तक से समझौता करने में परहेज नहीं किया,जिनका मुलायम सिंह से छत्तीस का आंकड़ा रहता था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों-यादव और मुस्लिम वोटरों का एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर रखा था, जिसको तोड़ना किसी भी विरोधी के लिए संभव नहीं रहा। 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी, तब से लेकर 2022 तक, जब उनका निधन हुआ,मुलायम ने तीन बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला। तीन बार सीएम बनने के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुलायम ने अपनी जगह बेटे को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। मुलायम की राजनीति हमेशा जमीन से जुड़ी रही गांव-गांव घूमना,कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनना,और जरूरत पड़ने पर गठबंधन की चाल चलकर सत्ता तक पहुंचना। लेकिन उनके बाद बेटे अखिलेश यादव ने जब पार्टी की कमान थामी, तो सवाल उठा कि क्या वे पिता की उस छाया से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस सवाल का जवाब कुछ हद तक दे दिया, लेकिन गहराई में उतरकर देखें तो तस्वीर और भी जटिल है।

नेताजी मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक पारी की शुरुआत जनता दल से हुई,लेकिन 1992 में अलग पार्टी बनाकर उन्होंने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अपना आधार बनाया। 1996 के लोकसभा चुनाव में सपा को 16 सीटें मिलीं, वोट शेयर करीब 20 प्रतिशत। फिर 1998 में 20 सीटें और 1999 में 26 सीटें। 2004 में मुलायम के नेतृत्व में पार्टी ने अपना रिकॉर्ड बनाया 35 सीटें, वोट शेयर 26.74 प्रतिशत। उस वक्त सपा अकेले लड़ी थी, गठबंधन का सहारा कम था। मुलायम की ताकत उनके व्यक्तिगत कद में थी। वे खुद रैलियों में उतरकर भीड़ को संबोधित करते, पहलवानी वाली भाषा में विरोधियों को ललकारते। उनकी सरकारों में यादव-मुस्लिम समीकरण मजबूत रहा, लेकिन कभी-कभी आंतरिक कलह भी सामने आई। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को 224 सीटें मिलीं और मुलायम ने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया। यह फैसला विरासत के हस्तांतरण का था,लेकिन उसी समय परिवार में दरारें भी दिखने लगीं।

अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने,तो उनकी छवि युवा, पढ़े-लिखे और विकास-उन्मुख नेता की बनी। लैपटॉप बांटने,सड़कें बनाने और बिजली व्यवस्था सुधारने जैसे कामों से वे लैपटॉप सीएम कहलाए। लेकिन 2017 में सपा को भारी झटका लगा,सिर्फ 47 सीटें बचीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी पांच सीटों पर सिमट गई, वोट शेयर गिरकर 18 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया। मुलायम के निधन के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश अकेले मैदान में उतरे। पिता का नाम अब भी ब्रांड था,लेकिन अखिलेश को खुद को साबित करना था। उन्होंने पीडीए पिछड़ा,दलित,अल्पसंख्यक का नारा दिया,बेरोजगारी,पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों पर हमला बोला। 2024 आया और अखिलेश ने वो कर दिखाया, जो पिता के समय में भी नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीत लीं। यह मुलायम के 2004 के 35 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला प्रदर्शन था। वोट शेयर बढ़कर 33.59 प्रतिशत हो गया पार्टी के 32 साल के इतिहास में सबसे ऊंचा आंकड़ा। 2019 की तुलना में वोट शेयर में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सिर्फ छह सीटें मिलीं,जबकि सपा ने 62 सीटों पर लड़कर बहुमत से ज्यादा प्रदर्शन किया। अखिलेश खुद कन्नौज से जीते, डिंपल यादव मैनपुरी से, और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी जीत हासिल की। लेकिन इस बार यादव उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ पांच रखी गई,जो मुलायम के समय में असंभव लगता था। अखिलेश ने मुस्लिम-यादव के पारंपरिक एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर पीडीए को व्यापक आधार दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य पिछड़ी जातियों का भी समर्थन मिला, जिससे सपा यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। अब 2027 में अखिलेश के पीडीए की परीक्षा होनी है।

खैर,लाख टके का सवाल यही है कि अखिलेश की राजनीति नेताजी मुलायम सिंह की राजनीति से कितना भिन्न भी थी, तो कहा जा सकता है कि 2024 तक अखिलेश को मुलायम सिंह जैसी कामयाबी नहीं मिल रही थी। दरअसल, मुलायम अक्सर खुद को केंद्र में रखते थे। 2004 में सपा ने यूपीए का साथ दिया था, फिर भी सीटें 35 ही रहीं। मगर अखिलेश ने 2024 में गठबंधन का फायदा उठाया, अपनी रणनीति से सीटें बढ़ाईं। उन्होंने टिकट बंटवारे में यादवों को सीमित रखकर संदेश दिया कि पार्टी अब एक जाति विशेष तक नहीं सिमटी। सपा के 86 प्रतिशत सांसद पिछड़े, दलित और मुस्लिम वर्ग से आए, जो पीडीए फॉर्मूले की सफलता दिखाता है। मुलायम के समय में पार्टी की सरकार होने पर भी इतनी सीटें लोकसभा में नहीं मिली थीं। अखिलेश ने विरोध में रहते हुए रिकॉर्ड बनाया। उनकी रैलियां युवाओं से भरी रहती हैं,सोशल मीडिया का इस्तेमाल वे बेहतर तरीके से करते हैं। पिता की तरह वे भी सड़क पर उतरकर जनता से जुड़ते हैं, लेकिन भाषा ज्यादा संयमित और मुद्दों पर केंद्रित रखते हैं। फिर भी गहराई में चुनौतियां बाकी हैं।

हालत बहुत बुरे हैं...

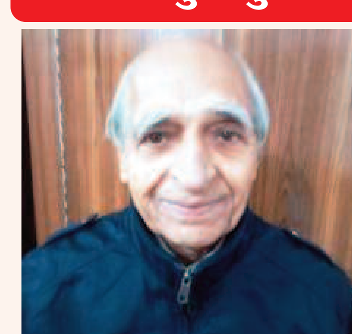

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक हरियाणा

जिधर भी देखो हालत बहुत बुरे हैं
परिवारों का हाल तो रोज देखते हो।
नेता लोग भ्रष्ट हैं रोज देखते हो
संसद की कार्रवाई आपके सामने है।
शहर के सीवर साफ सफाई देखी है?
राजनेता कितने ईमानदार हैं पता है
नकली दूध, घी, मिठाई भी देखी है
आदमी का व्यवहार भी देखा है!
पीने का पानी बहुत ही गंदा है
पानी बेचने वालों का चला धंधा है।
मोबाइल तो बच्चों की लाचारी है
हाथ में डिग्री है फिर भी बेकारी है।
नेताओं के लंबे-लंबे यहां भाषण है
वोट लेने के लिए देते यह राशन है!
किचन में लफड़ा ,कमर तोड़ महंगाई है
जो करेगा शिकायत उसकी शामत आई है
देश धर्म जाति के नाम पर बट गया है
चीन से डरा पाकिस्तान के आगे डट गया है।
यह सब देख लगता हालत खराब है
लेकिन सरकार कहती सब लाजवाब है।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारी बनाए गए बंधक

सुभाष बुड़ावन
वाला,रतलाम,मध्यप्रदेश

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना न केवल चिंताजनक है,बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में कड़ी टिप्पणी करना इस बात का संकेत है कि स्थिति सामान्य प्रशासनिक विफलता से कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है। जब न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं हो पा रही हो, तो निष्पक्ष चुनाव की कल्पना करना कठिन हो जाता है।

इस घटना में महिला अधिकारियों का भी शामिल होना इसे और संवेदनशील बनाता है। यह केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। अदालत को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा और कड़े निर्देश देने पड़े, तब जाकर अधिकारियों को मुक्त कराया जा सका। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहा या उसने अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई।

इलेक्शन कमिशन को जांच के लिए सीबीआई या नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की सहायता लेने का निर्देश देना भी यह दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय को राज्य सरकार की निष्पक्षता और क्षमता पर भरोसा नहीं रहा। यह स्थिति संघीय ढांचे के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में यदि राज्य प्रशासन पर भरोसा कमज़ोर पड़े,तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है।पूरे देश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ,लेकिन बंगाल से आई इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि प्रारंभिक चरण,यानी मतदाता सूची तैयार करने,में ही अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है,तो मतदान के दौरान संभावित गड़बड़ियों की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ऐसे परिदृश्य में यह मांग उठना स्वाभाविक है कि संवेदनशील राज्यों, विशेषकर जहां पहले भी चुनावी हिंसा के आरोप लगे हों,वहां केंद्रीय बलों की व्यापक तैनाती की जाए। बिहार जैसे राज्यों में, जहां जल्द चुनाव होने हैं, वहां सेंट्रल रिजर्व Police फोर्स और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

शौच-साहित्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

नगरपालिका के उस सुलभ शौचालय की ड्योढ़ी लांघते ही नासिका छिद्रों का साक्षात्कार उस सनातन अमोनिया से होता है,जो हड़प्पा की खुदाई से लेकर आज के डिजिटल इंडिया तक अपनी संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए हुए है। यहाँ की वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की वह सघनता है कि यदि कोई सिरफिरा वैज्ञानिक यहाँ माचिस की तीली का अग्नि-संस्कार कर दे,तो आधा जनपद तत्काल सदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाए और बचा हुआ आधा हिस्सा सीधे वैकुंठ की वीथिकाओं में स्वच्छ भारत का नारा लगाता मिले। इन पीली पड़ चुकी टाइल्स रूपी चर्म-पत्रों पर जो मूत्र-साहित्य रचा गया है,वह किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोध-प्रबंध से अधिक मर्मभेदी और कालजयी है। यहाँ की कुंडी-विहीन दीवारों पर पिंकी और बबलू के प्रेम का जो त्रिकोण बना है, उसके बीच से गुजरता तीर दरअसल उस शिक्षित बेरोजगारी का वैश्विक प्रतीक है, जिसने उस अज्ञात कलाकार को इस गंधमयी कंदरा में बैठकर अपनी सृजनशीलता विसर्जित करने पर विवश किया है। यहाँ का हर कोना एक ओपन प्रेस-कॉन्फ्रेंस है, जहाँ व्यवस्था से पराजित नागरिक अपनी पूरी भड़ास उन रिसते हुए नलों और टूटे हुए फ्लश-टैंकों के बीच ऐसे उड़ेलता है, मानो यही उसकी नियति का अंतिम डस्टबिन हो। यहाँ के बाथरूम कवि अपनी हताशा को शायरी का जामा पहनाकर समाज के पाखंड पर ऐसा करारा तमाचा जड़ते हैं, जिसकी गूंज और गंध दोनों ही असहनीय हैं।

इस लघु-ब्रह्मांड में समाज के हर वर्ग का अभिव्यक्ति का अधिकार पूरी नग्नता के साथ अट्टहास करता है। यहाँ दीवारों पर अंकित मोबाइल नंबरों की ऐसी जघन्य सघनता है कि यदि कोई टेलीकॉम कंपनी यहाँ अपना टावर लगा दे,तो पूरा जिला एक-दूसरे की जन्म-कुंडली बांचने लगे और गृह-युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। यहाँ लिखे गए काव्य और गालियों के बीच का फासला उतना ही सूक्ष्म है,जितना कि चुनाव से पूर्व के संकल्प-पत्र और शपथ ग्रहण के बाद की हकीकत के बीच होता है। वह टपकता हुआ नल और जाम पड़ी हुई नाली उस प्रशासनिक भ्रष्टाचार का सजीव और सचल विज्ञापन है, जिस पर संसद में भले ही मौन साध लिया जाए, किंतु यहाँ का सर्वहारा लेखक उस पर एक कालजयी मुक्तक लिखकर अपना नागरिक धर्म निस्पृह भाव से पूरा कर लेता है। दीवारों पर खिंची वे टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें किसी कुंठित आत्मा के ईसीजी जैसी प्रतीत होती हैं, जहाँ पॉलिटिक्स मुर्दाबाद के ऊपर किसी ने सपना, तू बेवफा है लिखकर यह वैज्ञानिक सत्य सिद्ध कर दिया है कि इस महान लोकतंत्र में सत्ता की उठापटक से बड़ा दुख आज भी व्यक्तिगत विरह ही है। यहाँ की सड़ांध में वह यथार्थवाद बसता है, जिसे हम अपनी ड्रॉइंग रूम की सोफिस्टिकेटेड चर्चाओं में इत्र छिड़ककर छुपाते हैं, पर जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र की सबसे तीखी और प्रामाणिक गंध है।

अनमोल वचन

सहयोग बहुत महंगी चीज है हर किसी से इसकी उम्मीद न रखें, क्योंकि.... बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

सद्भावना चौक के पास अज्ञात महिला की हत्या,दुष्कर्म के बाद वारदात की आशंका

चेहरा कुचला,शरीर पर कई चोट के निशान,सीसीटीवी में युवक के साथ दिखी थी महिला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

शहर के सद्भावना चौक के पास शुक्रवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव पास ही स्थित झोपड़ीनुमा मछली दुकान में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। महिला का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका जता रही है।

सीसीटीवी में युवक के साथ दिखी महिला : पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की,जिसमें महिला रात करीब 11 बजे एक युवक के साथ नजर आई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने पास में खाना खाया, जिसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी।

जमीन पर पटकने से गंभीर चोट

पुलिस का अनुमान है कि आरोपी ने महिला के बाल पकडक़र उसे जमीन पर पटक दिया,जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोट आई। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है,जो घटना की गंभीरता को दर्शाता है।

अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी राजेश अग्रवाल,एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो, सीएसपी राहुल बंसल सहित फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और जांच की।

पहचान और आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मृतका की पहचान कराने और सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

क्रूस हमारे जीवन के असली प्रेम का प्रतीक है

गुडफ्राइडे के दिन महागिरिजाघर में हुए विविध कार्यक्रम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

मसीही समाज पवित्र सप्ताह गुडफ्राइडे के दिन यीशु को क्रुसित कर सूली पर चढ़ाये जाने के दिन को याद कर भक्ति आराधना में लीन हैं। गुडफ्राइडे के अवसर पर नवापारा स्थित महागिरिजाघर में परम्परागत ढंग से विविध धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न हुए। पवित्र शुक्रवार के दिन नवापारा स्थित बेदाग ईश माता महागिरिजाघर में बिशप अंतोनिस बड़ा व पल्ली पुरोहित फादर जार्ज ग्रे कुजूर की अगुवाई में समस्त धार्मिक अनुष्ठान प्रारम्भ हुए। आज के दिन ही राजा पिलातयूस ने प्रभु यीशु को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाकर यीशु के ही कंधे पर क्रूस लादकर उन्हें कलवारी पहाड़ ले जाने का आदेश दिया था और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। प्रभु यीशु ने जिस तरह दुखभोग किया उन्ही पलों को याद कर दोपहर 2 बजे से क्रूस रास्ता कार्यक्रम शुरू हुआ। क्रूस रास्ता का संचालन गांधीनगर के नेतृत्व में पारा टोलों के लोगों द्वारा किया गया।

इसके पश्चात बिशप ने पवित्र शुक्रवार विशेष धर्मविधि के अनुष्ठानों को सम्पन्न कराते हुए कहा कि आज का दिन यीशु के बलिदान का दिन है वास्तव में क्रूस दोषी पापी को सजा नहीं क्षमा करने का संदेश देता है, क्रूस हमारे जीवन के असली प्रेम का भी प्रतीक है। इस दौरान पवित्र बाइबिल से दो पाठ का वाचन संत अन्ना सिस्टर्स बिरनिबेड़ा के द्वारा किया गया। प्रभु येशु के दुखभोग कथा का वाचन सेंट जेवियर फादर्स ने कर उन पलों का स्मरण किया। बीच-बीच में भक्तिमय गीतों की मनमोहक प्रस्तुति संत अन्ना सिस्टर्स बिरनी बेड़ा की टीम ने भक्तों के बीच माहौल को दुखभोगमय बना रही थी। इस अवसर इस अवसर पर बड़ी संख्या में मसीहिजन उपस्थित थे।

दरिमा-अम्बिकापुर एयरपोर्ट से दिल्ली-कोलकाता उड़ान शुरू

सांसद ने केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री का जताया आभार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा अंचल को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरिमा-अम्बिकापुर एयरपोर्ट से दिल्ली एवं कोलकाता के लिए हवाई सेवा प्रारंभ होने पर सरगुजा सांसद ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री Kinjarapu Ram Mohan Naidu से सौजन्य भेंट कर आभार व्यक्त किया। सांसद ने कहा कि यह पहल सरगुजा क्षेत्र के विकास, पर्यटन और व्यापार को नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं के और विस्तार को लेकर भी चर्चा की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि एयरपोर्ट के विकास और नई उड़ानों के लिए आवश्यक सभी कदम प्राथमिकता के साथ उठाए जाएंगे। इसके बाद सांसद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai से भी मुलाकात कर हवाई सेवा प्रारंभ होने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू करने हेतु आवश्यक उन्नयन कार्य कराने तथा अम्बिकापुर से दुर्ग तक वंदे भारत ट्रेन संचालित करने के लिए रेल मंत्रालय में पहल करने का आग्रह किया गया।

इस अवसर पर अंबिकापुर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री Rajesh Agrawal तथा भाजपा प्रदेश महामंत्री Akhilesh Soni भी उपस्थित रहे।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026...छत्तीसगढ़ की टीम ने मल्लखंभ में लहराया परचम,बालक-बालिका दोनों वर्ग चैंपियन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

खेलो इंडिया ट्राईबल गेम्स 2026 के अंतर्गत सरगुजा जिले के अम्बिकापुर के गांधी स्टेडियम में आयोजित डेमो खेल मल्लखंभ प्रतियोगिता का शानदार समापन शुक्रवार को हुआ। प्रतियोगिता में खिलाडिय़ों ने रोप मल्लखंभ,पोल मल्लखंभ,हैंगिंग मल्लखंभ, पिरामिड मल्लखंभ में एक से बढक़र एक करतब दिखाए। खिलाडिय़ों के प्रदर्शन पर वहां मौजूद दर्शकों द्वारा तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता के बाद विजेता टीम घोषित किया गया। आज हुई प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ विजेता घोषित की गई। विजेता टीमों को शनिवार को आयोजित मेडल सेरेमनी में मेडल प्रदान किया जाएगा।

ये रहे चैंपियन...

मल्लखंभ प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। राज्यों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर जीत के लिए दमखम लगाया। छत्तीसगढ़ की टीम ने बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 124.35 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 118.35 अंक के साथ सिल्वर एवं झारखण्ड की टीम ने 86.95 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बलिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 80.15 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 69.90 अंक के सिल्वर एवं झारखण्ड की टीम ने 49.80 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

आबकारी टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई,76 नशीले इंजेक्शन जब्त,2 आरोपी जेल भेजे

अजिरमा और दर्रीपारा में दबिश,लंबे समय से इंजेक्शन बेच रही युवती भी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

संभागीय आबकारी उडऩ्दस्ता टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए दो अलग-अलग मामलों में 76 नग नशीले इंजेक्शन जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में की गई। आबकारी टीम ने 2 अप्रैल को गश्त के दौरान अजिरमा बुधवारी बाजार स्थित पानी टंकी के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पूरनम विश्वकर्मा, निवासी कटकोना पटना जिला सूरजपुर बताया,जो वर्तमान में अंबिकापुर के कालीघाट क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था। उसके पास से प्लास्टिक झोले में रखे 22 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 22 नग एविल इंजेक्शन बरामद किए गए।

दर्रीपारा में युवती गिरफ्तार : 3 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर टीम ने जेल तालाब दर्रीपारा में घेराबंदी कर आराधना नामक युवती को पकड़ा। उसके पास से 20 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 12 नग एविल इंजेक्शन जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से इस क्षेत्र में नशीले इंजेक्शन बेच रही थी।

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई : दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (सी) के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

इलाके में बढ़ रहा नशे का असर : कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि जेल तालाब क्षेत्र नशेडिय़ों का अड्डा बनता जा रहा है, जिससे आसपास का माहौल खराब हो रहा है। लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई।

टीम की अहम भूमिका : इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक टी.आर. केहरी, मुख्य आरक्षक कुमारूराम, अशोक सोनी,नगर सैनिक रणविजय सिंह सहित महिला सैनिक चंद्रावती,राजकुमारी सिंह और नीरज चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि सरगुजा को नशा मुक्त बनाने के लिए टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।

बलरामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 537 शराबी चालकों सहित 7970 पर चालान,29.89 लाख रुपये वसूले

-संवाददाता-
बलरामपुर,03 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बलरामपुर-रामानुजगंज जिला पुलिस ने प्रथम तिमाही (जनवरी से मार्च 2026) में व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 7970 प्रकरणों में चालान काटे और ?29,89,900 की राशि वसूली। अभियान के तहत सबसे ज्यादा कार्रवाई शराब पीकर वाहन चलाने वाले 537 चालकों पर की गई। इसके अलावा बिना हेलमेट 2023 मामलों और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1659 मामलों में भी चालानी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर (भा.पु.से.) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में की गई। जिला पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ सख्त प्रवर्तन भी किया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि—

- दोपहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाएं।
- नाबालिगों को वाहन न चलाने दें।
- बिना लाइसेंस वाहन न चलाएं
- शराब या नशे की हालत में वाहन न चलाएं।
- हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें
- तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं
- वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें।

पुलिस ने कहा कि नियमों का पालन कर ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और सभी नागरिकों को जिम्मेदार व्यवहार अपनाना चाहिए।

पानी से भरे बाल्टी में गिरने से 11 माह के बच्चे की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

माता-पिता के साथ सोए 11 माह का बच्चा पानी से भरे बाल्टी में गिर गया। जब मां को नींद खुली तो होश उड़ गए। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। यहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार दीपक तिर्की उदयपुर के ग्राम झिरमिटी का रहने वाला है। वह पत्नी व बच्चों के साथ अंबिकापुर स्थित बिलासपुर रोड में किराए में रहकर चौकीदारी का काम करता है। गुरुवार को दीपक की नाइट ड्यूटी थी। ड्यूटी खत्म होने पर रात करीब 2.30 बजे दीपक घर आया। इसका 11 माह का बेटा अंश जो जगा था। थोड़ी देर उसके साथा खेलने के बाद उसे बीच में सुलाकर माता-पिता सो गए। रात करीब 4 बजे पत्नी सुनीता की नींद खुली तो बिस्तर पर बच्चा नहीं था। वह कमरे में उठकर उधर-उधर देखी तो कमरे में पानी से भरे बाल्टी में सिर के बल बच्चा गिरा था। उसे तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परसा और नवानगर मंडल प्रशिक्षण महाभियान का भव्य समापन अंबिकापुर में

भारत सिंह सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को किया प्रेरित,वहीं संजय मित्तल ने प्रशिक्षण की सराहना की...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत भाजपा मंडल परसा और नवानगर के संयुक्त प्रशिक्षण सत्र का समापन अग्रसेन भवन अंबिकापुर में संपन्न हुआ। समापन सत्र की अध्यक्षता अग्रवाल सभा सरगुजा के जिला अध्यक्ष संजय मित्तल ने की, जबकि विषय वक्ता के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया उपस्थित रहे। समापन सत्र को संबोधित करते हुए भारत सिंह सिसोदिया ने प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के युग में कार्यकर्ताओं का निरंतर प्रशिक्षण अनिवार्य है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाता है, बल्कि संगठन को मजबूत और अनुशासित बनाता है। सिसोदिया ने जोर देकर कहा कि प्रशिक्षण के बिना कार्यकर्ता केवल संख्या मात्र रह जाते हैं,लेकिन प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही भाजपा को राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को अपनाकर हम एकात्म मानववाद की दिशा में अग्रसर होंगे,जो हमें अन्य दलों से अलग करता है। इस अवसर पर अध्यक्ष संजय मित्तल ने भाजपा द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण महाभियान की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश की कोई अन्य राजनीतिक पार्टी इस पैमाने पर व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं चलाती। यही कारण है कि भाजपा के अनुशासित और प्रशिक्षित कार्यकर्ता संगठन को अद्वितीय ऊंचाइयों पर ले जाते हैं।

अंत में,विषय वक्ताओं और सत्र अध्यक्षों को शॉल, श्रीफल तथा स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष, परसा मंडल अध्यक्ष संतोष जायसवाल, नवानगर मंडल अध्यक्ष बाली चरण यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

C M Y K

मनेंद्रगढ़ बना उभरता मेडिकल हब...फिजियोथेरेपी कॉलेज का भूमिपूजन,इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई

मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज की नींव,50 सीटों पर होगा प्रवेश

- अब नहीं जाना पड़ेगा रायपुर : मनेंद्रगढ़ में ही तैयार होंगे डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट
- 'जायसवाल मॉडल' की झलक : मनेंद्रगढ़ में मेडिकल शिक्षा को मिली नई रफ्तार
- 14 करोड़ की सौगात : मनेंद्रगढ़ में बनेगा अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी कॉलेज
- मेडिकल हब बनने की ओर मनेंद्रगढ़ : फिजियोथेरेपी कॉलेज से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर
- सुस्ती पर भारी विकास : मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज से तेज हुई स्वास्थ्य क्रांति

-संवाददाता-
मनेंद्रगढ़,03 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में स्थित मनेंद्रगढ़ अब स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान स्थापित करता नजर आ रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के नेतृत्व में क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात मिली है, शुक्रवार को आमाखेरवा ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1393.71 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन का भूमिपूजन किया गया। इस आयोजन को क्षेत्र के विकास की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर: घर के पास ही उच्च शिक्षा-

मनेंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अब तक फिजियोथेरेपी और मेडिकल शिक्षा के लिए राजधानी रायपुर या अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता था, आर्थिक और सामाजिक रूप से यह कई परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण था, अब इस नए कॉलेज की स्थापना के साथ यह स्थिति बदलने जा रही है। विद्यार्थियों को अपने ही जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी,जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी, यह पहल ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।

'मनेंद्रगढ़ को मेडिकल हब बनाना हमारा लक्ष्य' - स्वास्थ्य मंत्री- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्यामबिहारी जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का उद्देश्य मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले को एक मजबूत मेडिकल हब के रूप में विकसित करना है, उन्होंने कहा कि यह कॉलेज केवल एक भवन नहीं बल्कि क्षेत्र के युवाओं के भविष्य का निर्माण केंद्र होगा, 2 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, मेडिकल कॉलेज की 50 सीटों पर भी इसी सत्र से पढ़ाई शुरू की जाएगी, उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई,50 सीटों पर प्रवेश

फिजियोथेरेपी कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र से 50 सीटों के साथ स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, यह कदम न केवल शिक्षा के अवसर बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय स्तर पर मेडिकल प्रोफेशनल्स तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा,मुख्य भवन के निर्माण तक कॉलेज का संचालन अस्थाई रूप से सिंधी कालरी एजुकेशन सोसाइटी,झगराखांड में किया जाएगा। इसके लिए SECL के साथ एमओयू किया गया है, जिससे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें।

मेडिकल क्षेत्र में बढ़ेंगे अवसर, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

फिजियोथेरेपी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के एक साथ विकसित होने से मनेंद्रगढ़ में एक मजबूत मेडिकल इकोसिस्टम तैयार होगा,इससे कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा,निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार की संभावना बढ़ेगी,यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देने में सहायक होगी।

'जायसवाल मॉडल' से तेज हुई विकास की रफ्तार

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि श्यामबिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है, पूर्व में जिन योजनाओं पर धीमी प्रगति देखी जा रही थी,वे अब तेजी से धरातल पर उतर रही हैं, रिक्त पदों पर नियुक्तियां,मेडिकल संस्थानों का विस्तार,नई परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन, इन सभी पहलुओं को 'जायसवाल मॉडल' के रूप में देखा जा रहा है,जिसमें त्वरित निर्णय और प्रभावी क्रियान्वयन प्रमुख है।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही अहम मौजूदगी

इस महत्वपूर्ण अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया, कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक रेणुका सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष चंपादेवी पावले,महापौर रामनरेश राय सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए,प्रशासनिक स्तर पर एमसीबी कलेक्टर डी राहुल वेंकट और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने परियोजना की रूपरेखा और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की।

प्रोजेक्ट की मुख्य बातें...

- कुल लागत : 1393 .71 लाख (लगभग 14 करोड़ रुपये)
- निर्माण एजेंसी : छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

प्रमुख सुविधाएं...

- ऑर्थोपेडिक्स आधारित फिजियोथेरेपी
- न्यूरोलॉजी सेवाएं
- कार्डियोलॉजी संबंधित उपचार

क्षेत्र के विकास की नई दिशा

फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना मनेंद्रगढ़ के लिए केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार भी बनेगा,इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा,बल्कि शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, यह परियोजना आने वाले समय में मनेंद्रगढ़ को छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेडिकल और एजुकेशन हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

हनुमान जन्मोत्सव पर मूर्ति स्थापना

-संवाददाता-
प्रतापपुर,03 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
पुलिस थाना प्रतापपुर परिसर में पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण कर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विधि-विधान से मूर्ति स्थापना की गई। इस दौरान भव्य धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना का आयोजन किया गया,जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना बनारस से आए विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बेदी पूजा एवं अन्य अनुष्ठानों के बीच सम्पन्न कराई गई। इस धार्मिक आयोजन से थाना परिसर अब नगर में आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। मूर्ति स्थापना के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में सूरजपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने भी पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा मंदिर निर्माण की सराहना करते हुए अपनी आस्था व्यक्त की। इस अवसर पर थाना प्रभारी अमित कौशिक, हरिशंकर तिवारी, राजेश यादव, राजेश तिवारी, विनोद परीडा, मंदिर समिति अध्यक्ष सतीश चौबे, व्यापारी संघ अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष अक्षय तिवारी, लालसंतोष सिंह, विंध्याचल गुप्ता, अंकुर जायसवाल, अमित पांडे सहित बड़ी संख्या में महिला-पुरुष एवं भक्तगण उपस्थित रहे।

प्रतापपुर में गूंजा 'जय श्रीराम', हनुमान जन्मोत्सव पर भक्ति में डूबा नगर

पक्की तालाब हनुमान मंदिर में जगराता,सुंदरकांड और भंडारे से सजी आस्था की भव्य झांकी

-संवाददाता-
प्रतापपुर,03 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर प्रतापपुर नगर का प्राचीन पक्की तालाब स्थित हनुमान मंदिर एवं सूर्य मंदिर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का केंद्र बना रहा। पूरे दिन और देर रात तक चले इस भव्य धार्मिक आयोजन ने नगर को पूरी तरह हनुमानमय कर दिया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान श्री संकट मोचन बजरंगबली के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर को विशेष आकर्षक सजावट और रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया था, जिसने पूरे वातावरण को दिव्य और अलौकिक बना दिया। भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर भगवान हनुमान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आयोजन के तहत रामायण पाठ एवं सुंदरकांड का सामूहिक आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्ति भाव से लीन नजर आए। इस वर्ष का आयोजन और भी खास रहा, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जगराता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध भजन गायिका बबीता विश्वास और प्रदीप विश्वास अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने भजनों की अमृत वर्षा से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरी रात भक्ति में डूबे रहे। स्थानीय भजन गायक राजेश गुप्ता ने भी अपने जस गीतों के माध्यम से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भक्ति गीतों की मधुर धुन और जयकारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा। 'जय श्रीराम' और 'हनुमान जी महाराज की जय' के उद्घोष से नगर का हर कोना भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बजरंगबली की भव्य झांकी रही, जिसमें भगवान हनुमान के विभिन्न स्वरूपों के साथ अन्य देवी-देवताओं की झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। इन झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और पूरे आयोजन को और अधिक आकर्षक बना दिया। इस अवसर पर प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने विधि-विधान से भगवान हनुमान के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इसके पश्चात वे जगराता कार्यक्रम में भी शामिल हुईं और भक्ति गीतों का आनंद लेते हुए तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आस्था, विश्वास और एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों को एक मंच पर लाकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का चुनरी भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समिति के सदस्यों ने पूरे आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया। इस भव्य आयोजन में समर कश्यप, संदीप रजक, राजेश कश्यप, भरत सोनी, व्यापारी संघ अध्यक्ष राजेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष मुकेश तायल, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अजीत शरण सिंह, धीरज गुप्ता, अंकुर जायसवाल, प्रफुल्ल गुप्ता, पप्पल जायसवाल, , जनपद पंचायत अध्यक्ष सुखमनिया आयाम, विक्रम नामदेव, अमन मित्तल, संजीत जायसवाल, शुभम कश्यप, विक्रम सिंह, मंदिर पुजारी दीपक दुबे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना के साथ-साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और जगराता में भाग लेकर अपने मन को भक्ति में सराबोर किया। प्राचीन पक्की तालाब स्थित हनुमान मंदिर एवं सूर्य मंदिर एक बार फिर नगर के प्रमुख आस्था केंद्र के रूप में स्थापित हो गया, जहां इस प्रकार के आयोजन ने धार्मिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान की। हनुमान जयंती के इस भव्य आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान बजरंगबली के प्रति लोगों की आस्था अटूट है। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं के मन में भक्ति और विश्वास की जो ज्योति जली,वह लंबे समय तक नगरवासियों के हृदय में प्रज्वलित रहेगी।

बीस साल से बसे ग्रामीण के घर पर चला वन विभाग का बुलडोजर...कार्यवाही पर पूर्व विधायक ने उठाए सवाल

भीषण गर्मी में गरीब के आशियाना उजाड़ने पर नाराज पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा अन्यायपूर्ण की गई कार्यवाही

-संवाददाता-
मनेंद्रगढ़/जनकपुर,03 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के वनभीषण गर्मी में उजड़ा आशियाना, पूर्व विधायक ने कहा–यह अन्यायपूर्ण और निंदनीय मंडल मनेद्रगढ़ अंतर्गत कुंवारपुर रेंज अंतर्गत फॉरेस्ट विभाग द्वारा जनकपुर के मनेंद्रगढ़ तिराहे में एक मकान फिर से तोड़ने की कार्यवाही की गई साथ ही कई घरों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। जिस पर क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कड़े शब्दों में आपत्ति जताते हुए लगातार वर्षों से काबिज ग्रामीणों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण, अमानवीय और निंदनीय कार्रवाई बताया है।लगातार वर्षों से काबिज ग्रामीणों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई पर सियासत गरमा गई है, उन्होंने कहा कि इस तरह एक व्यक्ति को निशाना बनाकर उसका घर तोड़ दिया गया, जबकि वह व्यक्ति पिछले लगभग 20 वर्षों से वहीं रहकर चाय बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। गर्मी के इस भीषण मौसम में ग्रामीण का आशियाना उजाड़ना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, पूर्व विधायक ने फॉरेस्ट विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिनका काम जंगलों की सुरक्षा करना है, वे हजारों पेड़ों की कटाई पर चुप हैं, लेकिन ग्रामीणों के घर गिराने में सक्रिय दिख रहे हैं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक ओर कांग्रेस की पूर्व सरकार ग्रामीणों को पट्टा देने का काम कर रही थी, वहीं वर्तमान बीजेपी सरकार में ग्रामीणों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जो सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है, गुलाब कमरो ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

CMYK

ऊपर मदिरा की दुकान, नीचे पैसे का मकान,
आवा संगी चली बैंक से पैसा लेके दारू झोंके...

■ बैंक के उपर बार,मंदिर के पास 'प्रीमियम' इंतजाम,बैकुंठपुर में विकास का नया मॉडल!

■ पैसा जमा करो,पैग उठाओ : बैकुंठपुर में अनोखी 'वन स्टॉप सुविधा'

■ स्कूल,मंदिर और बैंक के बीच वाइन शॉप, किसने बनाई ये 'परफेक्ट लोकेशन'?

■ बैकुंठपुर में विकास या व्यंग्य,जहां बैंक के नीचे बिक रहा 'नशा'

■ धर्म,शिक्षा और शराब का संगम,प्रशासन ने रचा अनोखा 'मॉडल'

■ मंदिर 200 मीटर,स्कूल पास में,फिर कैसे मिली शराब दुकान को मंजूरी?

■ लोकेशन या 'लापरवाही'? बैकुंठपुर में शराब दुकान पर उठे सवाल

■ सरकारी दफ्तरों के बीच 'प्रीमियम नशा'– प्रशासन की चुप्पी क्यों?

■ नियमों से इतर लोकेशन? बैकुंठपुर में प्रीमियम वाइन शॉप विवाद में

■ लोकेशन चयन पर पारदर्शिता की कमी, प्रशासन पर सवाल

-रवि सिंह-

कोरिया,03 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। बैकुंठपुर प्रीमियम शराब दुकान पर व्यंग्यात्मक प्रस्तुति ऊपर बोतल चमके ब्रांडेड, नीचे नोटों की बरसात, बैंक से निकले मेहनत का पैसा, शाम होते ही हो जाए साफ...सिस्टम ऐसा सेट हुआ है,जनता देखे बस तमाशा,दिन में बैंक की लाइन लंबी, रात में ठेके पर भाषा...कोरिया जिले के बैकुंठपुर में विकास की एक नई परिभाषा सामने आई है, यहां अब आम जनता को अलग-अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं–पैसा भी जमा करिए और उसी के नीचे से 'प्रीमियम' बोतल भी ले जाइए, जी हां, यूको बैंक के नीचे संचालित हो रही प्रीमियम वाइन शॉप ने वन स्टॉप सर्विस का ऐसा मॉडल पेश किया है,जो शायद नीति आयोग को भी प्रेरित कर दे।

आकर्षण के लिए फुल गुब्बारों से सजा प्रीमियम दुकान

शराब प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए भी प्रीमियम दुकान में व्यवस्था की गई है,यहां फूल गुब्बारों से मुख्य सीढ़ियों को सजाया गया है,मदिरा प्रेमियों को आते ही एक बेहतर एहसास हो,उन्हें स्वागत का भाव समझ में आए ऐसी पूरी कोशिश की गई है,अब समझने वाली यह बात है कि शराब दुकान के आकर्षण के लिए सजावट की क्या जरूरत,जहां इसका सेवन ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वहां इसकी बिक्री स्थल पर स्वागत बोर्ड समझ से परे है।

चारों ओर सरकारी दफ्तर,बीच में 'मनोरंजन केंद्र'

अगर आप सोच रहे हैं कि यह दुकान किसी सुनसान जगह पर होगी,तो आप गलत हैं,इसके आसपास ग्रामीण बैंक,पशु चिकित्सालय और समाज कल्याण विभाग का कार्यालय मौजूद है, यानि अगर कोई व्यक्ति बैंक का काम निपटाकर बाहर निकले और उसे अचानक तनाव महसूस हो,तो समाधान कुछ ही कदम दूर है,समाज कल्याण विभाग भी पास में है,शायद यह मान लिया गया हो कि कल्याण का दायरा अब थोड़ा व्यापक हो चुका है।

धर्म और 'ड्रिंक' का अद्भुत संगम

इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि विप्र समाज के आराध्य भगवान परशुराम के नाम पर बना चौक भी पास ही स्थित है, और अगर श्रद्धालु वहां से आगे बढ़ें, तो करीब 200 मीटर की दूरी पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, अब यह तो आस्था का विषय है कि कोई पहले मंदिर जाए या पहले प्रीमियम दुकान–या फिर दोनों का संतुलन बनाकर चले।

स्कूल के पास 'व्यावहारिक शिक्षा' का नया मॉडल-

इस वाइन शॉप से थोड़ी दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल भी संचालित है, बच्चे अब किताबों में सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि उसका व्यावहारिक प्रदर्शन भी देख सकेंगे, शिक्षा का यह नया मॉडल शायद नई शिक्षा नीति का अगला अध्याय बन सकता है जहां सिद्धांत और व्यवहार का संतुलन सिखाया जाएगा।

लोकेशन चयन:विज्ञान, कला या 'चमत्कार'?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस स्थान का चयन कैसे किया गया, क्या कोई विशेष सर्वे हुआ? क्या किसी समिति ने गहन अध्ययन किया? या फिर यह सब संयोग से हो गया? क्योंकि इतनी सटीक लोकेशन चुनना अपने आप में एक कला है–जहां बैंक, मंदिर, स्कूल और सरकारी दफ्तर–ऑल इन वन फ्रेम में आ जाएं।

नियमों की किताब:पढ़ी गई या सीधे बंद कर दी गई?-

सामान्यत: शराब दुकानों के लिए कुछ दिशा-निर्देश होते हैं–जैसे स्कूल और धार्मिक स्थलों से दूरी बनाए रखना, लेकिन बैकुंठपुर के इस मामले में ऐसा लगता है कि या तो नियमों की किताब किसी ने पढ़ी ही नहीं, या फिर पढ़कर इग्नोर कर दिया गया, अब यह तय करना मुश्किल है कि यह लापरवाही है या फिर अत्यधिक आत्मविश्वास।

प्रशासन की चुप्पी:रणनीति या असमंजस?-

इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, चुप्पी कभी-कभी बहुत कुछ कह देती है या तो जवाब नहीं है, या जवाब देने की जरूरत नहीं समझी जा रही, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, तो प्रशासन को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए।

स्थानीय जनता का आक्रोश:'प्रीमियम' विरोध की तैयारी-

क्षेत्र के लोगों में इस फैसले को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है, लोगों का कहना है कि यह न केवल सामाजिक दृष्टि से गलत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर पड़ेगा, कुछ लोगों ने इसे संवेदनहीन निर्णय बताया है, तो कुछ इसे प्रशासनिक विफलता मान रहे हैं।

व्यंग्य के पीछे छिपा गंभीर सवाल-

अगर व्यंग्य को थोड़ी देर के लिए अलग रखें, तो यह मामला वास्तव में गंभीर है, क्या नियमों का पालन किया गया? क्या स्थानीय लोगों की राय ली गई? क्या संवेदनशील स्थानों का ध्यान रखा गया? ये सवाल केवल बैकुंठपुर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं।

विकास की दिशा या निर्णय की भूल?-

आज विकास शब्द का इस्तेमाल हर फैसले के लिए किया जाता है, लेकिन क्या विकास का मतलब यह है कि सुविधा के नाम पर हर चीज कहीं भी स्थापित कर दी जाए? या फिर विकास का मतलब संतुलन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी भी होता है?

जवाब जरूरी है-

बैकुंठपुर का यह मामला अब केवल एक वाइन शॉप का मुद्दा नहीं रह गया है, यह प्रशासनिक पारदर्शिता, नियमों के पालन और सामाजिक जिम्मेदारी का सवाल बन चुका है, अब जरूरत है कि, प्रशासन स्पष्ट रूप से स्थिति बताए, यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई करे, और भविष्य में इस तरह के निर्णय लेते समय स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आखिरकार, प्रीमियम शब्द केवल बोतल पर अच्छा लगता है–निर्णयों पर नहीं।

जयमरगा के गढ़पहाड़ की गुफा में प्रागैतिहासिक काल के हैं आदिमकालीन शैलचित्र

-संवाददाता-

जशपुरनगर, 03 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जशपुर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण तो है ही पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी समृद्ध है। यहां की प्राकृतिक छटा सहज ही लोगों को आकर्षित करती है। यहां पर प्राकृतिक तौर पर निर्मित झरने, गुफाएं, पहाड़ों का आकर्षण ऐसा है कि पर्यटक खींचे चले आते हैं। इसी तरह की एक जगह है ग्राम जयमरगा का गढ़पहाड़। यहां पर प्राकृतिक तौर पर निर्मित गुफा में

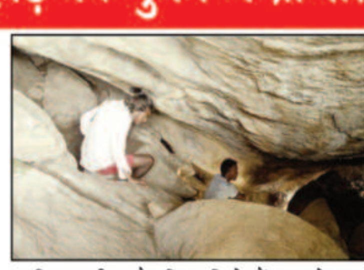

आदिमकालीन शैलचित्र मिले हैं। इससे पता चलता है कि आदिमानव यहां पर निवास करते रहे होंगे। उनकी बनाई कलाकृति आज भी यहां पर मौजूद हैं। जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर जयमरगा ग्राम है। ग्राम पंचायत डड़गांव का यह आश्रित ग्राम जयमरगा मनोरा विकासखंड के अंतर्गत आता है। ग्राम की आबादी लगभग 1400 है। इस ग्राम तक पहुंचने के लिए सड़कें बनी हुई है। जयमरगा पहुंचने पर यहां की गढ़पहाड़ पर लगभग 300 मीटर तक चढ़ाई करने के बाद इस गुफा तक पहुंचा जा सकता है। इस गुफा में ही आदिमकालीन शैलचित्र बने हुए हैं। ग्रामीण यहां पर पूजा भी करते हैं। पुरातत्ववेत्ता डॉ. अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा ने बताया कि जयमरगा गाँव में प्रागैतिहासिक स्थलों की भरमार है। यहाँ पहाड़, जंगल और नदी के कारण प्रागैतिहासिक मनुष्यों के जीवन के लिए आवश्यक भोजन, पानी और आश्रय की उपलब्धता थी। इस गाँव में एक प्रागैतिहासिक शैल चित्र गुफा है,जहाँ मध्य पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। शैल चित्र में मानव आकृतियाँ,पशु आकृतियाँ,ज्यामितीय आकृतियाँ और कुछ अज्ञात आकृतियां दिखाई देती हैं। ये चित्र लाल और सफेद रंग से बने हैं।

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0 /अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है,कि आवेदक अमित पाण्डेय आठ प्रमेश्वर पाण्डेय, अभिषेक पाण्डेय आ0 प्रमेश्वर पाण्डेय, निवासी देवीगंज रोड़,अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर,जिला- सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर -02 नोहल्ला देवीगंज रोड़, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 448/1 रकबा 0.00 1/2 भूमि को अनावेदक/क्रेता आलोक जायसवाल आ0 स्व0 कन्नीलाल जायसवाल, जाति जायसवाल, निवासी पुलिस लाईन रामानुजगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा छ0ग0 के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.04.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0 /अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका पूनम सोनी पति राजू सोनी, जाति सोनार, निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की शीट नंबर- 02 मोहल्ला-सत्तीपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 747/1 रकबा 0.02 एकड़ भूमि की लीज अवधि समाप्ति तिथि 31.03.2026 है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का लीज अवधि बढ़ाये जाने हेतु आवेदन मय मेंटनेंस खसरा की प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 07.04.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

कार्यालय नगरपालिका परिषद् सूरजपुर जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

Phone :- 07775-266355/Fax :- 07775-266956 / Email Id:- nagarpalikasurajpur@gmail.com

क्रमांक/05/न0पा0प0/2026-27 सूरजपुर, दिनांक 02/04/2026

- मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना -

एतद् द्वारा नगर पालिका परिषद् सूरजपुर अंतर्गत अधोसंरचना मद में विभिन्न निर्माण कार्य पी. डब्ल्यू.डी. (भवन/नाली एस.ओ.आर. 01.01.2015/रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2025) से प्रभावशील की दरों से अधिक/बराबर/कम प्रतिशत दर से सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों से चार लिफाफा पद्धति से मुहरबंद लिफाफा में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त लिफाफे में कार्य का नाम, टी.डी.आर./एफ.डी.आर.क का विवरण एवं दिनांक लिफाफे के उपर अंकित होने पर ही लिफाफा स्वीकार किया जाएगा।

1. निविदा पंजीकृत डाक से प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय - 17/04/2026 सायं 4.00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 17/04/2026 सायं 4.30 बजे तक

क्र0	कार्य का विवरण	अनु0 लागत (वार्षिक)	अमानत राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये)
01	वार्ड क्र0- 17 राजा ढोढी में टाईल्स,चबुतरा एवं रैलिंग कार्य । (द्वितीय)	0.85	2000.00	300.00
02	वार्ड क्र0-18 राजेश देवांगन ड्राईवर घर के पास सी.सी. रोड निर्माण कार्य। (द्वितीय)	1.79	2000.00	300.00
03	वार्ड क्र0-18 रामलाल चेरवा घर के पास सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य । (द्वितीय)	1.91	2000.00	300.00
04	वार्ड क्र0 - 07 पीपल चौक मे नाली निर्माण कार्य । (तृतीय)	4.92	5000.00	750.00
05	वार्ड क्र0-08 जगरनाथ साहू घर से अशोक बंगाली घर तक सी.सी. नाली निमार्ण कार्य (तृतीय)	3.11	3500.00	750.00

निविदा फार्म विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकेगें । विस्तृत जानकारी हेतु न0पा0 कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट https:/uad.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् सूरजपुर
जिला- सूरजपुर (छ0ग0) सूरजपुर.

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग अम्बिकापुर
निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक. 1885 / NIT -01/2026-27/ व. ले.लि. / अम्बिकापुर दिनांक 01/04/2026

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि-: 22/04/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि -: 28/04/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि -: 29/04/2026 पूर्वाहन 11.00 बजे तक
निविदाकारों की श्रेणी -: एकल पंजीयन में पंजीकृत द वर्ग ठेकेदार
भवन एस.ओ.आर -: 01.01.2015 लागू दिनांक 06.04.2016 तक संशोधित

एन.आई.टी. क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रु. में) बैंक सेल्वेन्सी (रू. में) निविदा प्रपत्र की कीमत (रू. में) कार्य की अवधि
1 T0001	नवीन शासकीय महाविद्यालय धौरपुर में शौचालय निर्माण कार्य	4.66 3495.00 69900.00 750.00 04 माह वर्षा ऋतु
1 T 0002	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बिकापुर के वर्कशॉप, सीढ़ियों, विद्युत विभाग का मरम्मत और पेंटिग कार्य	9.91 7433.00 148650.00 750.00 03 माह वर्षा ऋतु सहित
1 T0003	सैनिक स्कूल मेण्ड्रकला में चार पहिया वाहन पार्किग का निर्माण कार्य	9.03 6773.00 135450.00 750.00 04 माह वर्षा ऋतु सहित

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.eg.nic.in/pwdraipur ×ð´ Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। एवं निविदा संबंधित शर्तों का अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

-मुख्य शर्तें-

-1 पूर्व जमा अमानत राशि का समायोजन नही किया जायेगा। अमानत राशि किसी भी राष्टीयकृत बैंक का अधेहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम से होना अनिवार्य है जो निविदा जारी होने की तिथि से मान्य किया जायेगा ।
2.निविदा प्रपत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ ठेकेदार का उपयुक्त श्रेणी एकल पंजीयन की प्रति, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, मालसेवा कर कार्यालय का पंजीयन एवं चूकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेंसी की मूल प्रति से सत्यापन कराना आवश्यक, नोटरी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जावेगा।
3. प्रगतिरत कार्यो की सूचि वर्ग बस एवं द वर्ग में पंजीकृत निविदाकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
वर्ग अ.ब.स एवं द वर्ग में पंजीकृत ठेकेदारों को शपथ पत्र एनेक्शर-3 में प्रस्तुत करना आवश्यक है एवं अ वर्ग ठेकेदार को बिड केपिसिटी प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नही की जावेगी।
4. निविदा प्रपत्र के लिए आवदेन पत्र के साथ ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत फार्म टु-बी की मूल प्रति से सत्यापन कराना आवश्यक अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नही की जावेगी।
5 सभी निविदाकारों से भवन एवं अन्य सनिर्माण एवं कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1 प्रतिशत देयक की राशि उपकर के रूप में काटी जावेगी। (अतिरिक्त विशेष शर्त संलग्न है)
6.कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना होगा एवं समानुपातिक प्रगति देना होगा, अन्यथा कार्य उनके व्यय एवं जोखिम पर बिना समय दिये समाप्त कर दिया जावेगा।
7. आबंटन एवं साख पत्र उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जावेगा।
8.अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
9. निविदा तिथि में किसी भी दिन अवकाश होने पर अगली तिथि को कार्यवाही की जायेगी।
10. निविदा को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
11.सशर्त निविदा स्वीकृत नही किया जायेगा।
नोट :-
उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय / स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जायें।

जी नंबर-262700029/2

कार्यपालन अभियंता
ल ने.वि. (भ/स) संभाग अधिकापुर

2023 में अतिक्रमण, 2026 में NOC
और अब खुद विभाग ने किया निरस्त
तीन साल में बदली पूरी कहानी

- 2023:जब नहर की जमीन पर निर्माण को बताया गया अतिक्रमण
- दस्तावेजों में स्पष्ट था मामला,फिर भी कार्रवाई क्यों अटकी?
- हाई कोर्ट तक पहुंचा विवाद,आदेश के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
- 2026:अचानक बदली सरकारी राय, जारी हुआ अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- फाइलों का यू-टर्नः एक ही मामले में चार अलग-अलग फैसले
- मीडिया के खुलासे के बाद बढ़ा दबाव,प्रशासन आया बैकफुट पर
- न्यूज़ का असर:जल संसाधन विभाग ने खुद रद्द किया एनओसी

- 'अपरिहार्य कारणों' का हवाला, लेकिन असली वजह अब भी साफ नहीं
- फिर खड़ा हुआ सवाल–अतिक्रमण है या वैध निर्माण?
- प्रशासनिक विश्वसनीयता पर संकट,जनता में बढ़ा अविश्वास
- स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
- राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक लापरवाही–क्या है असली कारण?
- अब आगे क्या:कार्रवाई होगी या फिर फाइलों में दबेगा मामला?
- नहर विवाद बना सिस्टम की परीक्षा, जवाब का इंतजार जारी

-रवि सिंह-

कोरिया, 03 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के भांडी क्षेत्र में नहर किनारे निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल एक स्थानीय जमीन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक निर्णयों, विभागीय समन्वय, राजनीतिक प्रभाव और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बनकर सामने आया है, तीन वर्षों में इस मामले ने जिस तरह करवट बदली–अतिक्रमण से वैधता और फिर वैधता से पुनः निरस्तीकरण तक–उसने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

मामले की शुरुआत:2023 में 'अतिक्रमण' की पुष्टि

वर्ष 2023 में ग्राम भांडी स्थित नहर किनारे किए गए निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आई, जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग की जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि संबंधित भूमि नहर की है और उस पर किया गया निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, विभागीय दस्तावेजों और रिपोर्टों में भी इसे अवैध निर्माण माना गया, प्रशासन ने प्रारंभिक स्तर पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, इस दौरान यह मामला केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया।

राजनीतिक संरक्षण में फंसा न्याय

नहर पर बना चौक या फाइलों का खेल?

भांडी का 'कर्म-चौक' या फाइलों का चक्रव्यूह?

जमीन,दस्तावेज और विवाद की गहराई...

नहर की जमीन पर निर्माण होने के कारण यह मामला संवेदनशील था, नहर भूमि सामान्यतः सार्वजनिक उपयोग और जल प्रवाह के लिए आरक्षित होती है, ऐसे में उस पर स्थायी निर्माण को लेकर नियम सख्त होते हैं, राजस्व अभिलेखों और विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज स्थिति के अनुसार, जिस भूमि पर निर्माण हुआ, वह जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है, यहीं से विवाद गहराया–एक ओर विभागीय रिपोर्ट अतिक्रमण बता रही थी, दूसरी ओर निर्माण पक्ष अपनी वैधता के दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था।

मामला पहुंचा न्यायालय:आदेश भी जारी

जैसे-जैसे विवाद बढ़ा, मामला न्यायालय तक पहुंच गया, हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश जारी हुआ,न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि नहर की भूमि पर अवैध निर्माण है,तो उसे हटाया जाना चाहिए,इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक फाइलों में नोटिंग,पत्राचार और रिपोर्ट का सिलसिला चलता रहा,लेकिन अतिक्रमण हटाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया।

प्रशासनिक सुस्ती या दबाव? कार्रवाई क्यों रुकी

यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि जब न्यायालय का आदेश भी आ चुका था, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सूत्रों के अनुसार,विभागों के बीच समन्वय की कमी, जिम्मेदारी तय न होना और संभावित राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं,फाइलों में लगातार बदलाव और अलग-अलग रिपोर्टों ने भी स्थिति को उलझा दिया।

2026 में अचानक बदला रुख:'अनापत्ति' का खेल

वर्ष 2026 की शुरुआत में इस मामले में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जल संसाधन विभाग द्वारा संबंधित निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, यह वही निर्माण था जिसे 2023 में अतिक्रमण बताया गया था, इस फैसले ने पूरे मामले को विवादित बना दिया,सवाल उठने लगे कि क्या जमीन की स्थिति बदल गई? क्या नए दस्तावेज सामने आए? या फिर विभागीय स्तर पर कोई दबाव काम कर रहा था?

राजनीतिक और सामाजिक पहलू

मामले में राजनीतिक एंगल से भी इनकार नहीं किया जा रहा है, अलग-अलग समय पर निर्णय बदलना,फाइलों का रुख बदलना,कार्रवाई का टलना इन सबने यह संकेत दिया है कि मामला केवल तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव से भी जुड़ा हो सकता है।

फाइलों का 'यू-टर्न':अतिक्रमण से अनापत्ति तक

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पहलू फाइलों का 'यू-टर्न' रहा, एक ही मामले में पहले अतिक्रमण की पुष्टि, फिर हटाने की सिफारिश, उसके बाद अनापत्ति जारी और अब पुनः निरस्तीकरण, इस तरह के बदलाव ने प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मीडिया में खुलासा और बढ़ता दबाव

लगातार खबरों के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को सामने लाया गया, नहर पर निर्माण की तस्वीरें, विभागीय रिपोर्टों के विरोधाभास, कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होना,इन सभी तथ्यों ने जनता के बीच चर्चा को और तेज कर दिया, मीडिया रिपोर्ट्स के बाद प्रशासन पर जवाब देने का दबाव बढ़ा।

न्यूज़ का असर : विभाग ने खुद रद्द किया एनओसी

आखिरकार 23 मार्च 2026 को जल संसाधन विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए अपने ही जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया, दस्तावेज़ में स्पष्ट उल्लेख है कि 6 फरवरी 2026 को जारी NOC को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जा रहा है,यह निर्णय सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि पहले लिया गया फैसला या तो त्रुटिपूर्ण था या फिर परिस्थितियों के दबाव में लिया गया था।

अब फिर वही सवाल:आखिर सच क्या है?

एनओसी निरस्त होने के बाद मामला फिर शुरुआती स्थिति में पहुंच गया है, अब सवाल यह है कि क्या निर्माण वास्तव में अतिक्रमण है? यदि हां, तो अब तक हटाया क्यों नहीं गया? और यदि नहीं, तो पहले अतिक्रमण क्यों बताया गया? इन सवालों के जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हैं।

प्रशासनिक विश्वसनीयता पर बड़ा असर

इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंचाई है, जब एक ही मामले में बार-बार निर्णय बदलते हैं, तो यह संदेश जाता है कि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है,जिम्मेदारी तय नहीं है और बाहरी प्रभाव संभव है, विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में स्पष्ट नीति और जवाबदेही आवश्यक है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया:भरोसा डगमगाया

स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर असंतोष और भ्रम की स्थिति है, लोगों का कहना है कि यदि अतिक्रमण था,तो हटाया जाना चाहिए था,यदि वैध था,तो शुरुआत में कार्रवाई क्यों हुई और यदि गलती हुई, तो जिम्मेदार कौन है, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों से गलत संदेश जाता है और अन्य अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा मिल सकता है।

कानूनी स्थिति: आगे की राह क्या?

अब जब एनओसी निरस्त हो चुका है,तो प्रशासन के सामने स्पष्ट विकल्प है, अतिक्रमण की पुष्टि कर कार्रवाई करना, न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराना यदि ऐसा नहीं हुआ, तो मामला फिर न्यायालय की शरण में जा सकता है।

जिम्मेदारी तय होगी या नहीं?

सबसे अहम सवाल यही है कि इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार कौन है? क्या गलत रिपोर्ट तैयार की गई? क्या दबाव में निर्णय लिया गया? या फिर प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही हुई? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक यह मामला अधूरा ही रहेगा।

सिस्टम की परीक्षा बना नहर विवाद

कोरिया का यह नहर अतिक्रमण मामला अब एक मिसाल बन चुका है जहां एक साधारण जमीन विवाद ने प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया, तीन साल में बदलते फैसलों ने यह दिखा दिया कि, पारदर्शिता की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है, और जवाबदेही के बिना सिस्टम कितना कमजोर पड़ जाता है, अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है–क्या सच सामने आएगा, या यह मामला फिर फाइलों में दब जाएगा?

छात्रावासों में कानूनी जागरूकता अभियान : बच्चों को बताया अधिकार और सुरक्षा के नियम

पॉक्सो एक्ट की जानकारी- बच्चों को सिखाया सुरक्षा का मूल मंत्र

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः, 202601020700133

विषय- ब-121 मामले की श्रेणी- राजस्व सन- 2025 2026
फतेहपुर प.ह.न. 00028 [(हे0)]
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार -बादशाह,
अनावेदक पक्षकार -छ0ग0शासन

ईश्तहार

आवेदक बादशाह आ0 अब्दुल वाहिद व अन्य, निवासी ग्राम फतेहपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदकगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम फतेहपुर स्थित खाता क्रमांक 514 में दर्ज खसरा नंबर 42, 374, 614, 623/3, 623/4, 656, 897, 898, 900, 902, 903, 972 कुल खसरा नंबर 12 कुल रकबा 4.927 हे0 तथा खाता क्रमांक 457 में दर्ज खसरा नंबर 18, 452/1, 452/2, 452/4, 721/3, 889/2, 899 कुल खसरा नंबर 07 कुल रकबा 2.923 हे0 भूमि तथा खाता क्रमांक 460 में दर्ज खसरा नंबर 1274, 1275 कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 1.513 हे0 भूमि तथा खाता क्रमांक 460 में ही दर्ज खसरा नंबर 1, 470, 523, 1280, 1282, 1428, 1431, 1439, 1441 कुल खसरा नंबर 09 कुल रकबा 2.521 हे0 भूमि तथा बिना खाता के दर्ज खसरा नंबर 690, 726/1, 1097/3, 626/1 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 1.743 हे0 भूमि ग्राम फतेहपुर में ही अलग-अलग खाता बनकर अलग-अलग बी-1 में दर्ज है। जिसको एक खाता में एक साथ बी-1 में दर्ज किये जाने हेतु बसरा संशोधन किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जॉच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 10.04.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27/01/2026 को जारी किया जाता है।

सील

उमेश्वर सिंह बाज
तहसीलदार,अंबिकापुर

-संवाददाता-

सूरजपुर,03 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के तत्वावधान में पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, सूरजपुर में एक महत्वपूर्ण कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यह कार्यक्रम प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीता वार्नर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ,कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यवहार न्यायाधीश अंजलि पाण्डेय ने की,जिन्होंने छात्रों को सरल भाषा में कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश श्रीमती अंजलि पाण्डेय ने पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों को विस्तार से समझाया, उन्होंने बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' के बीच का अंतर व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से बताया,उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की असहज या अनुचित हरकत को तुरंत अपने अभिभावकों,शिक्षकों या विश्वसनीय व्यक्ति को बताना चाहिए। बच्चों को यह भी समझाया गया कि चुप रहना समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है।

जागरूकता ही सुरक्षा का आधार

यह कार्यक्रम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा,बल्कि छात्रों के भीतर आत्मविश्वास और जागरूकता का भाव भी उत्पन्न किया,पॉक्सो एक्ट,साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों की समझ से छात्र अब अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।

साइबर अपराध से बचाव: सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा

छात्रों को आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर अपराधों की जानकारी दी गई,न्यायाधीश महोदया ने बताया कि आजकल ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं,जैसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी,फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल,बैंक केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी,परिजनों की दुर्घटना का झूठा भय दिखाना,वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेल करना। उन्होंने छात्रों को समझाया कि ऐसे मामलों में डरने या घबराने की जरूरत नहीं है,बल्कि तुरंत परिवार,शिक्षक या पुलिस को सूचना देनी चाहिए।

यातायात नियमों की समझ: जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख

कार्यक्रम में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई,छात्रों को बताया गया कि वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है,वाहन का पंजीयन और बीमा जरूरी है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना दंडनीय अपराध है,दुर्घटना की स्थिति में कानूनी जिम्मेदारियां तय होती हैं,साथ ही चोरी के वाहन खरीदने-बेचने के गंभीर कानूनी परिणामों के बारे में भी जानकारी दी गई।

निःशुल्क विधिक सहायता: हर नागरिक का अधिकार

कार्यक्रम के अंत में छात्रों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई,छात्रों को बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर या जरूरतमंद व्यक्ति भी कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकता है, इसके लिए नालसा का टोल फ्री नंबर 15100 उपलब्ध है,जिससे सीधे मदद ली जा सकती है।

कार्यक्रम में रही सक्रिय भागीदारी

इस जागरूकता कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षक श्री रामज्ञान सिंह एवं श्री भुवनेश्वर सिंह सहित पैरालीगल वॉलंटियर्स सत्य नारायण, उमेश कुमार रजवाड़े, चिरंजीव लाल रजवाड़े एवं सद्दाम हुसैन की उपस्थिति रही, सभी ने छात्रों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी।

समापन समारोह में बॉक्सर मेरीकॉम और फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया हुए शामिल

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन जनजातीय प्रतिभाओं के लिए ऐतिहासिक और यादगार मंच : मुख्यमंत्री साय

जनजातीय प्रतिभाओं को मिला राष्ट्रीय मंच,खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बना नए अवसरों का द्वार : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर,03 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित दीनदयाल आडिटोरियम रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो जोश और ऊर्जा देखने को मिली, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश की आदिवासी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने और उनकी खेल क्षमता को सामने लाने का अनूठा अवसर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके विजन और मार्गदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ। साथ ही केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के निरंतर सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज देश के खेल मानचित्र में प्रमुख स्थान पर स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब यह गेम्स प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज और खेल का रिश्ता सदियों पुराना है। तीरंदाजी, दौड़ और कुश्ती जैसे खेल जनजातीय जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देश की एकता, संस्कृति और कौशल का महाकुंभ बनकर उभरा है। देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय खिलाड़ियों ने इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह आयोजन आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने और खेलों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खिलाड़ियों ने केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि साहस और उत्कृष्टता की नई कहानियां रचने के लिए प्रतिस्पर्धा की है। उन्होंने यह साबित किया है कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं,बल्कि बस्तर,सरगुजा, झारखंड और पूर्वोत्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में भी भरपूर है। समारोह में मुख्यमंत्री साय ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कर्नाटक,द्वितीय स्थान ओडिशा और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने कुल 19 पदक (03 स्वर्ण, 10 रजत और 06 कांस्य) हासिल किए हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि स्विमिंग में अनुष्का भगत ने 4 रजत पदक जीते,निखिल खलखो और न्यासा पैकरा ने भी पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। एथलेटिक्स में सिद्धार्थ नागेश ने स्वर्ण और रजत पदक जीते, वहीं अन्य खिलाड़ियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वेटलिफ्टिंग में निकिता ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश की बेटियों का मान बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

साय ने पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा भी की। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक के लिए 2 लाख रुपये, रजत के लिए 1.5 लाख रुपये और कांस्य के लिए 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं दलीय स्पर्धाओं में स्वर्ण के लिए 1 लाख रुपये, रजत के लिए 75 हजार रुपये और कांस्य के लिए 50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी खिलाड़ियों, कोच, आयोजन समिति, अधिकारियों और सहयोगी संस्थाओं को इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जनजातीय खेलों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर मेरीकॉम और फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए।

साथ ही केबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा,छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव विक्रम सिसोदिया, छत्तीसगढ़ राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुमोना सेन,खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार,रायपुर कमिश्नर संजीव शुक्ला, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में देश भर से आए खिलाड़ी उपस्थित थे।

रायपुर रेल मंडल का शानदार प्रदर्शन...2025-26 में 4983 करोड़ का हुआ राजस्व प्राप्त

रायपुर,03 अप्रैल 2026। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व, माल लदान,यात्री सुविधाओं और तकनीकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन उपलब्धियों की जानकारी मीडिया से साझा की। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेलवे ने आधारभूत संरचना के विकास,नई रेल लाइनों के निर्माण, चौथी लाइन परियोजनाओं में प्रगति और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया। साथ ही यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई पहलें भी की गईं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रायपुर मंडल ने राजस्व,संरक्षा, तकनीकी नवाचार एवं यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय रेल में एक आदर्श मंडल के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.87 प्रतिशत (लगभग 4 प्रतिशत) की वृद्धि हासिल की है और 46.44 मिलियन टन लदान कर 4983 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रायपुर मंडल को 46.33 मिलियन टन लदान का लक्ष्य दिया गया था। रायपुर मंडल ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 44.73 मिलियन टन लदान कर 4818 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था। इस उपलब्धि के पीछे आधुनिक लोडिंग अवसंरचना, ग्राहक-केंद्रित नीतियां, डिजिटल पहल तथा विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रायपुर रेल मंडल द्वारा कोयला, स्टील प्लांट के लिए रॉ मटेरियल, पिग आयरन,फिनिश्ड स्टील,आयरन ओर,सीमेंट,फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर आदि का माल लदान किया गया है। रायपुर मंडल नए अवसर बनाने में सफल रहा है, साथ ही भारतीय रेल के प्रमुख शीर्ष मंडलों में 9वें स्थान पर रहा है।

सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी
जवानों ने ध्वस्त किए नक्सलियों के दो डंप,भारी मात्रा में हथियार बरामद

जगदलपुर,03 अप्रैल 2026। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ की 85वीं बटालियन ने एंटी-नक्सल अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के दो डंप बरामद किए हैं। यह ऑपरेशन गंगालूर थाना क्षेत्र के पेद्दाजोजेर और लेण्ड्रा के घने जंगलों में चलाया गया, जहां संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की छुपाई गई सामग्री को खोज निकाला। बरामद किए गए डंप में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री शामिल है, जिसमें 303 राइफल,स्टेन गन, बीजीएल राउंड,डेटोनेटर,जिलेटिन और वायर जैसे उपकरण शामिल हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार,यह सामग्री नक्सलियों द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से छुपाकर रखी गई थी,जिसे समय रहते जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई को क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है,जिससे उनकी गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ के 4 आईपीएस ट्रेनिंग के लिए जाएंगे हैदराबाद

डीजीपी ने चार जिलों में प्रभारी एसपी किए नियुक्त,मनीषा ठाकुर संभालेंगी रायपुर की कमान

रायपुर,03 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने 4 जिलों में प्रभारी एसपी की नियुक्ति की है। इन जिलों के एसपी के इंडक्शन ट्रेनिंग पर जाने के कारण यह व्यवस्था की गई है। प्रभारी एसपी की नियुक्ति का आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ कैडर के 4 आईपीएस अधिकारी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, पंकज चंद्रा, वेदव्रत सिरमौर और विजय पांडेय को इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए चुना गया है।

आईपीएस श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा रायपुर ग्रामीण में,विजय पांडेय जांजगीर-चांपा, पंकज चंद्रा कोंडागांव, वेदव्रत सिरमौर गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक

हैं। यह उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में आयोजित किया जाएगा।

किसे कहां की मिली जिम्मेदारी : रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी मनीषा ठाकुर रावटे को सौंपी गई है। जांजगीर-चांपा का प्रभार विमल कुमार बैस को दिया गया है। कोंडागांव की जिम्मेदारी प्रभारी कप्तान त्रिलोक बंसल को सौंपी गई है।गरियाबंद में प्रभारी एसपी के रूप में नीरज चंद्राकर को जिम्मेदारी दी गई है।

ट्रेनिंग अवधि तक रहेगा प्रभार

इन एसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में अब संबंधित जिलों का कानून-व्यवस्था संचालन किया जाएगा। डीजीपी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक मूल अधिकारी ट्रेनिंग से वापस नहीं लौटते, तब तक ये चारों अधिकारी अपने-अपने जिलों में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

आधुनिक पुलिसिंग के लिए अहम है इंडक्शन ट्रेनिंग

आईपीएस अधिकारियों की इंडक्शन ट्रेनिंग हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित की जाती है। इस प्रशिक्षण के लिए देशभर से आईपीएस अधिकारियों का चयन किया जाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग को आईपीएस अधिकारियों के करियर ग्राफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। करीब डेढ़ महीने तक चलने वाली इस ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी आधुनिक पुलिसिंग,कानून-व्यवस्था और प्रशासन के नए आयामों को सीखते हैं।

हत्या की धमकी और मारपीट-तोड़फोड़ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज

महासमुंद,03 अप्रैल 2026। जिला कांग्रेस में खुलकर दिखी पार्टी की गुटबाजी की वजह से पार्टी की चर्चा हो रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय महासमुंद में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। कांग्रेस के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष निर्मल जैन और वर्तमान जिला उपाध्यक्ष व पार्षद विजय साव पर एफआईआर दर्ज हुई है। निर्मल जैन पर अश्लील गाली-गलौच और मारपीट की धारा 296,115 (2) बीएनएस के तहत दर्ज केस दर्ज हुआ है। वहीं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष विजय साव पर अश्लील गाली, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और कुर्सी टेबल तोड़ने को लेकर 296,115(2),351(3),324(2) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक,जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता रखी गई थी। इस दौरान कांग्रेसजनों की उपस्थित काफी कम थी। बस इतनी सी बात पर कांग्रेसियों में आपस में जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष निर्मल जैन और वर्तमान जिला उपाध्यक्ष,पार्षद विजय साव के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कार्यालय के अन्दर कुर्सियों और कांच के बर्तनो को भी तोड़ा-फोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि,महंगाई को लेकर जिला अध्यक्ष की प्रेसवार्ता आयाजित थी। वार्ता खत्म होते ही कांग्रेस पदाधिकारियों में आपस में मारपीट और तोड़फोड़ हो गई।

थाना परिसर से ट्रक चोरी,ड्राइवर गिरफ्तार

रायपुर,03 अप्रैल 2026। ट्रक चोर 6 घंटे के भीतर पकड़ा गया है, ट्रक क्रमांक सीजी/07/ए जेड/5831 के नो-एंट्री में प्रवेश करने पर यातायात भनपुरी पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की गई थी ट्रक चालक द्वारा चालान नही पटाने पर ट्रक को यातायात थाना भनपुरी में खड़ा किया गया था। दिनांक 02.04.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि,कोई अज्ञात व्यक्ति यातायात थाना भनपुरी में खड़े किये हुए ट्रक क्रमांक सीजी/07/ए जेड/5831 को चोरी कर फरार हो गया है। जिसपर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 194/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चोरी की घटना को पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) आकाश मरकाम,सहायक पुलिस आयुक्त उरला पूर्णिमा लामा तथा थाना प्रभारी खमतराई को अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल तथा उसके आस-पास के सी.सी.टी.व्ही. फुटेज का अवलोकन कर आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे, इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा सी.सी.टी.व्ही. कैमरो के फुटेजों का अवलोकन करते हुए अज्ञात आरोपी को ट्रक के साथ राजनांदगांव के रास्ते में जाता देखा गया था।

सरेंडर के बाद अब जेल से मुख्यधारा... जेल में बंद माओवादियों का होगा पुनर्वास,डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताई नक्सल उन्मूलन की नई रणनीति

रायपुर, 03 अप्रैल 2026। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में राज्य सरकार अब एक नई रणनीति पर काम कर रही है। सक्रिय नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के बाद अब साय सरकार जेलों में बंद माओवादियों को मुख्यधारा में लाने की योजना तैयार कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों में 500 से अधिक माओवादी मारे गए हैं, जबकि करीब 3 हजार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर पुनर्वास का रास्ता चुना। इसके अलावा लगभग 2 हजार नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब

सरकार का फोकस उन कैद माओवादियों पर है, जो छोटे-छोटे मामलों में जेल में बंद हैं। सरकार ऐसे नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने और पुनर्वास देने की योजना बना रही है, ताकि वे सामान्य जीवन में लौट सकें। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य की पुनर्वास नीति केवल कागजी नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। डिप्टी सीएम ने बताया कि बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के जरिए भी समाज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि जब जंगलों से नक्सलियों का पुनर्वास संभव है, तो जेलों से भी यह प्रक्रिया सफल हो सकती है।

अमित शाह के चुनावी दौरे के दौरान साथ-साथ रहेंगे विजय शर्मा,बंगाल के लिए मिली जिम्मेदारी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में उतरकर जनता को अपने पक्ष में रिझाने की पूरी पूरजोर ताकत लगा रही है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष में बैठी टीएमसी फिर से सरकार बनाने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही है तो दूसरी ओर भाजपा भी यहां पर सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भाजपा ने बंगाल चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को प. बंगाल चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बनाया गया है।

बैंककर्मी दोस्त ने वकील से 3 करोड़ ठगे...स्कॉटलैंड की महिला बनकर चैटिंग,कैंसर हॉस्पिटल खोलने 103 करोड़ के डीडी क्लियरेंस की आड़ में फ्रॉड

बिलासपुर,03 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कैंसर अस्पताल खोलने के नाम पर वकील से करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को स्कॉटलैंड से 103 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेजने का झांसा दिया। इस रकम को क्लियर कराने के नाम पर अलग-अलग प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के बहाने 3 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। काफी समय तक डिमांड ड्राफ्ट क्लियर नहीं होने पर पीड़ित को संदेह हुआ। जांच करने पर खुद के साथ ठगी होने का एहसास हुआ। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पीड़ित के बैंक कर्मी दोस्त पर ठगी के आरोप लगे हैं, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है।

बैंक कर्मी दोस्त पर ठगी का आरोप : जानकारी के मुताबिक पीड़ित वकील का नाम अरुण मिश्रा है,जबकि उसका दोस्त एचडीएफसी बैंक में काम करता है। आरोप है कि उसने ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

भरोसा जीतने नकली सबूत भी पेश किए : यह भी बताया रहा है कि आरोपी ने भरोसा जीतने के लिए फर्जी दस्तावेज और ट्रांजैक्शन से जुड़े नकली सबूत भी पेश किए।

इससे पीड़ित को पूरी तरह विश्वास हो गया कि रकम जल्द मिल जाएगी,लेकिन उसे पैसे नहीं मिले।

प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में निगम 120 करोड़ पीछे तारीख बढ़ने से 15 करोड़ का नुकसान

रायपुर,03 अप्रैल 2026। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में इस बार नगर निगम टारगेट से काफी पीछे रह गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय 475 करोड़ रुपए के टारगेट के मुकाबले अब तक करीब 350 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं। इस तरह निगम करीब 120 करोड़ रुपए पीछे चल रहा है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन वसूली को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। 31 मार्च को करीब 25 करोड़ रुपए की वसूली का अनुमान था, लेकिन वसूली महज 7 करोड़ रुपए के आसपास ही सिमट गई। इसकी बड़ी वजह संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करना माना जा रहा है। तिथि बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में करदाताओं ने भुगतान टाल दिया, जिससे निगम को एक ही दिन में लगभग 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। निगम की वसूली पर सबसे अधिक प्रभाव बड़े बकायादारों के कारण पड़ा है। जानकारी के अनुसार शहर में बड़े संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर करीब 150 करोड़ रुपए बकाया है।

शराब नष्टीकरण की कमाई से गोदाम अधिकारी और शराब माफिया मालामाल

रायपुर में भी हो सकता है जहरीली शराब कांड...

रायपुर,03 अप्रैल 2026। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, विधानसभा ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार जीरो टारलेंस देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब माफिया सरकार के खिलाफ काम कर रही है और सरकार को बदनाम करवने की नीयत से एक्सपायरी शराब को नष्ट करने के बजाय शराब माफिया को बेचकर करोड़ों की कमाी कर रही है। आबकारी प्रभारी अधिकारी के आगे प्रशासन मतमस्तक है जिसके कारण आम जनता को जीरो टारलेंस देने की बात जो कि केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है । आबकारी विभाग के अधिकारी अपने विरोधियों,साथियों और कर्मचारियों पर घोटाला करने का आरोप लगा कर सरकार को गुमराह कर रही है। वर्तमान में शराब घोटाला एवं भ्रष्टाचार में आबकारी प्रभारी अधिकारी शामिल है जिसका उदारहण रायपुर में देका जा सकता है। गोवा से आए शराब माफियाओं को आबकारी प्रभारी अधिकारी

द्वारा खुलेआम बिना और भय के राजनैतिक व उच्चाधिकारियों के संरक्षण में हर माह करोड़ों रूपये का भष्टाचार किया जा रहा हा। रायपुर स्थित सिलतरा विदेशी शराब गोदाम है जो भाजपा नेता की पत्नी का है उसे आबकारी प्रभारी अधिकारी ने किराए से लिया है। जिसके कारण उन्हें राजनैतिक व उच्चधिकारियों का सरंक्षण प्राप्त है। जिसके कारण वे कई वर्षों से लगातार भष्टाचार में सम्मिलित व अनेकों शिकायतें होने के मान भी कोई कार्यवाही हुआ और न ही पद से हटाया गया है। ये अध्कारी इस कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ है। रायपुर सिलतरा विदेशी गोदाम / बिलासपुर गोदाम का सी.सी.टी.वी. कैमरा जानबूझकर जब शराब की अफरा तफरी करनी होता है और शराब माफियाओं को शराब की सप्लाई देनी होती है तब बंद कर दिया जाता है। नष्टीकरण में कमेटी के लोग केवल खानापूर्ति करने के लिए पंचनामा बनाकर अवैध शराब बिकी में सहयोग करते है। रायपुर सिलतरा विदेशी शराब गोदाम/बिलासपुर गोदाम से प्रतिमाह निर्धारित समय पर फुट (बैकेज) क्षतिग्रस्त गाडियों एवं विभिन्न कंपनियों से वसूली की जानकारी निर्धारित समय में जिला कार्यालय को नही भेजा जाता है।

पुदुच्चेरी में पीएम मोदी का मेगा रोड शो

मुख्यमंत्री रंगासामी के साथ दिखाई ताकत, उमड़ा जनसैलाब

पुदुच्चेरी,03 अप्रैल 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पुदुचेरी में रोड शो के जरिए राज्य विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन के समर्थन में प्रचार किया और जनता से आशीर्वाद मांगा। पुदुचेरी की सड़कों पर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। पुदुचेरी में चुनावी माहौल को गरमाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला अजंता सिग्नल से शुरू होकर कामराजर प्रतिमा तक चला। लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को तय करने में करीब एक घंटे का समय लगा। इस दौरान पीएम के साथ मुख्यमंत्री और एआईएनआरसी नेता एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमसिवायम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और जनता ने उन पर फूलों की बारिश की। रोड शो के दौरान पूरे शहर में भाजपा और एआईएनआरसी के झंडे नजर आ रहे थे। सडकों के दोनों ओर खड़े समर्थकों ने

भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह-जगह पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पुलिस ने पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी गई। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से चुनाव में गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलेगी। इससे पहले पिछले महीने भी पीएम ने पुदुचेरी का दौरा किया था और वहां 2700 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन किया था। केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और पीएम की लोकप्रियता के दम पर एनडीए इस बार भारी बहुमत की उम्मीद कर रहा है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के तहत एआईएनआरसी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गठबंधन के अन्य साथी अन्नाद्रमुक और लक्ष्य जननायक पार्टी को 2-2 सीटें दी गई हैं। 9 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है।

देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं घबराहट में बुकिंग न करें : इंडियन ऑयल

एलपीजी की आपूर्ति सामान्य,करीब 28 लाख सिलेंडर प्रतिदिन हो रहे हैं डिलीवर

नई दिल्ली,03 अप्रैल 2026। देश की सबसे बड़ी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने शुक्रवार को कहा कि देश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और प्रतिदिन करीब 28 लाख एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। इसलिए घबराहट में बुकिंग न करें। आईओसी ने एक बयान में कहा कि पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बावजूद भारत में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति स्थिर एवं पर्याप्त है और घरेलू उपलब्धता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। कंपनी ने कहा कि देश में रोजाना लगभग 28 लाख सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, जो सामान्य स्तर के बराबर है। घबराहट से प्रेरित मांग को रोकने के लिए उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे समय से पहले बुकिंग न करें। कंपनी के अनुसार वह प्रतिदिन करीब 28 लाख एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति कर रही है, जो मौजूदा तनाव से पहले के सामान्य स्तर के अनुरूप है। आईओसी ने बताया कि करीब 87 फीसदी 'रीफिल बुकिंग' डिजिटल माध्यमों से की जा रही हैं, जबकि सही उपभोक्ता तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड (ओटीपी) आधारित प्रणाली से वितरण की पुष्टि की जा रही है। उपभोक्ताओं को एसएमएस (संदेश) और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) जैसे डिजिटल माध्यमों से एलपीजी 'रीफिल बुक' (सिलेंडर

फिर भरवाने) करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सोशल मीडिया और उपभोक्ता शिकायतों के जरिए कुछ एलपीजी वितरकों को अनियमितताओं की जानकारी मिली है। काला बाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए विभिन्न विभागों के कई दल एलपीजी वितरक केंद्रों पर अचानक निरीक्षण कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 7,500 से अधिक निरीक्षण किए गए और 141 वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है,जिनमें 5 को निलंबित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों और अन्य तेल एवं गैस विपणन कंपनियों के साथ मिलकर करीब 68 हजार छापे भी डाले गए हैं। इस संबंध में 855 प्राथमिकी दर्ज की गई और 48 हजार से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए। कंपनी ने कहा कि वह एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता, वितरण में पारदर्शिता एवं अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध : अमित शाह

असम,03 अप्रैल 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दुधनाई के कॉलेज ग्राउंड मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवार टंकेश्वर राभा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वह असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार देश से अवैध विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्वालपाड़ा जिले की सभी चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में असम को अशांत बनाए रखा और राज्य की संस्कृति

के संरक्षण के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि भाजपा असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने का प्रयास कर रही है। सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा शासन में लगभग 10 हजार लोगों को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापस लाया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 1.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी पांच वर्षों में यदि भाजपा सत्ता में लौटती है तो राज्य में कोई हिंसात्मक घटना नहीं होगी। उन्होंने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु नए उद्योग स्थापित करने का वादा भी किया। अपने संबोधन के अंत में शाह ने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में एक भी वोट न देने की अपील करते हुए असम में विकास और स्थिरता के लिए भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया।

असम चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हुंकार.....

एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकालेगी एनडीए सरकार

असम,03 अप्रैल 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारपेटा में विधानसभा चुनावों से पहले एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच तीखा अंतर दिखाया। रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए सरकार ने सुरक्षा और सुशासन सुनिश्चित करते हुए भारत की संस्कृति, परंपराओं और विरासत को मजबूत करने के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के विकास के लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'दोहरे इंजन वाली सरकार' के प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए ने एक दशक के भीतर असम को बदलने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और इसे राज्य के लिए पुनर्जागरण का दौर बताया। असम गण परिषद (अगप) उम्मीदवार दीपक कुमार दास के समर्थन में बारपेटा में एक रैली

को संबोधित करते हुए, आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने लंबे शासनकाल के दौरान राज्य और उसके लोगों की रक्षा करने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में कांग्रेस 60 वर्षों से सत्ता में थी। लेकिन इसने घुसपैठ, हिंसा और दंगों को ही बढ़ावा दिया। इसने स्थानीय संस्कृति और विरासत को खतरे में डाल दिया। उन्होंने एआईयूडीएफ पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह घुसपैठियों को प्रोत्साहित कर रही है और उसका लक्ष्य इनके समर्थन से सत्ता पाना है। आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ मिलकर राज्य की संस्कृति और विरासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि राजग सरकार राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घुसपैठिये की पहचान करके उसे खदेड़ दिया जायेगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला राजग 'लव और लैंड जिहाद' तथा जनसांख्यिकी में किसी भी प्रकार का बदलाव सहन नहीं करेगा। आदित्यनाथ ने कहा कि राजग ''विरासत-विकास'' को एक साथ सुनिश्चित करेगा, जैसा कि उसने उन राज्यों में किया है जहां वह सत्ता में है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम में एक बड़ा बदलाव आया है और मैं इस चुनाव में राजग के लिए आपके निरंतर समर्थन का आग्रह करता हूं। बारपेटा से अपने उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ''चुनाव से पहले ही मैदान से भाग गई है''। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नौ अप्रैल को होगा और मतगणना चार मई को होगी।

मालदा कांड की साजिश का पर्दाफाश

AIMIM और ISF नेताओं की गिरफ्तारी से गरमाई बंगाल की सियासत

नई दिल्ली,03 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने राज्य की कानून-व्यवस्था और न्यायिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मालदा के कालियाचक इलाके में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान तैनात सात न्यायिक अधिकारियों को उग्र भीड़ ने घेर लिया और लगभग 9 घंटों तक बंधक बनाए रखा। बुधवार को हुई इस घटना के दौरान भीड़ ने न केवल अधिकारियों का रास्ता रोका,बल्कि पथराव और हिंसा भी की। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि देर रात भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद ही इन अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इस घटना ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जिसमें कई कट्टरपंथी और क्षेत्रीय दलों के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता मोफक्करुल इस्लाम की गिरफ्तारी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस्लाम को इस पूरे घटनाक्रम का 'मुख्य साजिशकर्ता' करार दिया है। उन्हें बागडोगरा एयरपोर्ट से उस समय हिरासत में लिया गया जब वे राज्य से बाहर भागने की फिराक में थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि मोफक्करुल इस्लाम ने ही भीड़ को संगठित किया और उन्हें न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ उकसाने में सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस अब उनके कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य संपर्कों की जांच कर रही है ताकि इस संगठित विरोध के पीछे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

डॉक्टर ने बचाई एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला यात्री की जान,सीएम ने की सराहना

इंफाल,03 अप्रैल 2026। मणिपुर के सेनापति जिले की एक डॉक्टर ने टोक्यो से नई दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान 21 साल की एक यात्री की जान बचाई। इंफाल के अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट, बबीना स्पेशलिटी हॉस्पिटल में

क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉ. लोनी लिरिना उस फ्लाइट में सफ़र कर रही थीं। इस दौरान एक युवा महिला को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और फ्लाइट क्रू ने मेडिकल मदद के लिए अनाउंसमेंट किया। इसके तुरंत बाद, डॉ. लिरिना उस यात्री की मदद के लिए आगे आईं। जांच करने पर, उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट, नेबुलाइजेशन और जरूरी दवाएं देने की सलाह दी, ताकि मरीज की हालत स्थिर हो सके। डॉक्टर की तेजी और सही समय पर लिए गए फैसले की वजह से, महिला की हालत 30 मिनट के अंदर ही काफ़ी बेहतर हो गई। तुरंत उचित देखभाल मिलने के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। फ्लाइट सुरक्षित रूप से नई दिल्ली में लैंड हुई।

भारत की समुद्री ताकत में इजाफा...नौसेना से जुड़ा आईएनएस तारागिरी

राजनाथ सिंह बोले...हम एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति

विशाखापत्तनम,03 अप्रैल 2026। भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में शुक्रवार को एक नया अध्याय जुड़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम स्थित नेवल डॉकयार्ड में स्वदेशी अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी और आईएनएस अरिदमन को नौसेना में शामिल कराया। इस समारोह में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी समेत अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा...'जब भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, भारतीय नौसेना ने हमारे वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। हमारी नौसेना ने यह साबित कर दिया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने

समय के साथ भारत का समुद्र से रिश्ता और मजबूत हुआ : रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री ने कहा...''ये शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का साक्षी रहा है, इसलिए विशाखापट्टनम से आईएनएस तारागिरी कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की रणनीतिक वास्तविकताओं ने समुद्र में हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया है। ' उन्होंने कहा...'हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय हितों से जुड़े महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों, चोक पॉइंट्स और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने नागरिकों और व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए विश्व स्तर पर हर संभव कदम उठा सकती है। यही क्षमता भारत को एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति बनाती है।

राजनाथ कहा, 'जब हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो उस परिकल्पना में नौसेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा वाला हमारा देश, जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, समुद्र से अलग अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता। हमारे लगभग 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी समुद्र पर निर्भर करती है।

हाथियों का कहर...तीन लोगों को कुचलकर मार डाला

रामगढ़,03 अप्रैल 2026। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने शुक्रवार की सुबह तीन लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में ईंट भट्ठा पर काम करने वाले दो मजदूर और एक बुजुर्ग ग्रामीण शामिल हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में भय और वन विभाग के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। पहली घटना बांदा गांव की है, जहां तड़के सुबह करीब चार बजे ईंट भट्ठा पर काम करने वाले दो मजदूर धीरज भुइयां और जुगल भुइयां शौच के लिए निकले थे। इसी दौरान हाथियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और पटक-पटक कर मार डाला। धीरज मूल रूप से पतरातू के तालाटांड़ का रहने वाला था, जबकि जुगल रामगढ़ के कुजू का निवासी था। दूसरी घटना मुरपा गांव में हुई, जहां 80 वर्षीय रामदेव

साव सुबह-सुबह महुआ चुनने के लिए घर से निकले थे। हाथियों ने उन पर हमला कर दिया और कुचलकर उनकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि 12 हाथियों का यह झुंड बोकारो के जंगलों से होते हुए रामगढ़ जिले के रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभा राष्ट्र की अमूल्य पूंजी : राष्ट्रपति

नई दिल्ली,03 अप्रैल 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देश के युवाओं,विशेषकर जनजातीय समुदाय के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्र की अमूल्य सामाजिक पूंजी बताते हुए उन्हें खेलों में सक्रिय भागीदारी और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया है। एक लेख के माध्यम से अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के ग्रामीण और वन क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक प्रतिभा को उचित प्रशिक्षण और संसाधनों के जरिए निखारकर देश खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। राष्ट्रपति ने जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों की सहज खेल प्रतिभा का उल्लेख करते हुए कहा कि ये बच्चे सीमित संसाधनों के बावजूद प्रकृति के बीच अपने खेल संसार का निर्माण कर लेते हैं। मिट्टी, पेड़ों, बीजों और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके वे खेल के साधन तैयार करते हैं और पूरे उत्साह के साथ खेलते हैं। उन्होंने

कहा कि यह स्वाभाविक रुझान और ऊर्जा यदि आधुनिक प्रशिक्षण और सुविधाओं से जुड़ जाए, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने में सक्षम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए ओडिशा की 15 वर्षीय खिलाड़ी अंजलि मुंडा का उल्लेख किया, जिसने 'खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026' में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक जीते और देशभर के युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।

मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश : चुनाव आयोग

नई दिल्ली,03 अप्रैल 2026। चुनाव आयोग ने 2026 के राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों पर भी लागू होगी और इस दिन के लिए किसी भी प्रकार की वेतन कटौती नहीं की जाएगी। आयोग ने शुक्रवार को कहा कि असम, केरल,पुडुचेरी,गोवा,कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा–पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 135बी के तहत प्रत्येक मतदाता, जो किसी भी संस्थान, उद्योग या व्यवसाय में कार्यरत है।

राघव चड्ढा ने आआपा हाईकमान पर दागे सवाल

कहा...मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है...

चंडीगढ़,03 अप्रैल 2026। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाए जाने से आहत सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सवाल दागे हैं। आआपा ने राज्यसभा सचिवालय से राघव के स्थान पर अशोक मित्तल को नियुक्त करने की सिफारिश की है। मित्तल जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। पंजाब में वर्ष 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राघव आआपा का प्रमुख चेहरा रहे हैं। पिछले कुछ समय से वह पंजाब की राजनीति से दूर हैं। राघव चड्ढा ने आज सुबह एक वीडियो जारी किया। इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं, '' खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। मुझे जब-जब बोलने का मौका मिलता है तो मैं आम आदमी के मुद्दे उठाता हूं। संसद में ऐसे मुद्दों पर बोलता हूं

जिन्हें आमतौर पर सदन में उठाया नहीं जाता।'' उन्होंने सवाल किया कि क्या जनता के मुद्दे उठाना, जनता के मुद्दों पर बात करना अपराध है। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया,कोई गलती कर दी? चड्ढा ने कहा कि यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को यह लिखकर दिया है कि राघव चड्ढा के सदन में बोलने पर रोक लगा दी जाए। बोलने का मौका न दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा। मैं जब बात करता हूं तो देश के आम आदमी की बात करता हूं। संसद में एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, टोल व बैंक लूट का मुद्दा उठाया। मिडिल क्लास से हो रही लूट, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार रिचार्ज करवाती हैं आदि पर चर्चा की। उन्होंने कहा,'' यह मुद्दे उठाने के बाद आम आदमी का फायदा हुआ लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ। मेरी आवाज को कोई क्यों बंद करना चाहेगा। आप लोग मुझे असीमित प्यार देते हैं। मेरा हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे ही मेरा हाथ और साथ थामे रखिएगा। छोड़िएगा मत। मैं आप से हूं, आपके लिए हूं। जिन लोगों ने संसद में बोलने का हक छीन लिया उनके लिए कहना चाहूंगा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना,मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।''

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साईं ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)